● वर्ष-6
● अंक-95
रायपुर, मंगलवार
17 नवंबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-6>> देवउठनी एकादशी

नशे के मामलों में सुनवाई की रफ्तार धीमी?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-राज्यों से पूछा, कब तक बनेंगी विशेष अदालतें?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से कहा है कि वे एनडीपीएस एक्ट के तहत गंभीर अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए 449 विशेष अदालतें स्थापित करने की दिशा में हुई प्रगति पर नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने केंद्र की ओर से पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की इस बात पर ध्यान दिया कि विशेष अदालतें स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए आदेशों के पालन में अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है। जस्टिस बागची ने कहा, यह मामला तीन जजों की बेंच के सुनने लायक है। उन्होंने बताया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं हैं। बेंच ने कहा कि वह सुओ मोटो (स्वत: संज्ञान लेने वाले) मामले को कुछ हफ्तों के लिए टाल रही है। यह मामला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाने से जुड़ा है। बेंच ने कहा कि इस पर दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियों से पहले सुनवाई की जा सकती है। अदालत ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे एनआईए और एनडीपीएस एक्ट के तहत लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष अदालतें बनाने की दिशा में हुई प्रगति पर नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। इससे पहले, बेंच ने पूरे देश में नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों में चिंताजनक वृद्धि और एनडीपीएस एक्ट के तहत लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई थी।



एसआईआर पर सुको पहुंचे राहुल: चुनाव आयोग से मांगे 48 सवालों के जवाब

नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच विवाद तेज होता जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है। इसमें चुनाव आयोग को 48 लिखित सवाल भेजने की अनुमति मांगी गई है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से हलफनामे के जरिए जवाब देने की मांग की गई है।



याचिका में आरोप लगाया गया है कि देशभर में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान एकतरफा फैसले लिए गए, मतदाताओं के नाम हटाए गए और चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल में बिना उचित मंजूरी के बदलाव किए गए। विपक्षी नेताओं ने इन सभी मामलों पर चुनाव आयोग से स्पष्ट जानकारी मांगी है। कांग्रेस ने पूछा है कि कितने फैसलों पर दोनों चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से असहमत थे? इसके अलावा, देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने का फैसला किसने लिया था? राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं का मुख्य सवाल यह है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की जानकारी, सहमति या मंजूरी के बिना आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल किया? चुनाव आयोग ने 26 अक्तूबर को दाखिल जवाबी हलफनामे और 14 नवंबर को दाखिल पूरक हलफनामे में कहा था कि एसआईआर से जुड़े आदेश तीन सदस्यीय आयोग के सर्वसम्मत फैसले के बाद जारी किए गए थे।

चुनाव अधिकारियों से मांगा जवाब

अर्जी में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से भी जवाब मांगा गया है। राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने मांग की है कि फरवरी 2025 से अक्तूबर 2026 के बीच इन दोनों चुनाव आयुक्तों ने एसआईआर, ECINET, फॉर्म-6 या अदालत में दाखिल अपीलों को लेकर कब-कब लिखित आपत्ति, असहमति या विरोध दर्ज कराया, इसकी पूरी जानकारी दी जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग को इस संबंध में रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराने चाहिए।

बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा

तमिलनाडु से ओडिशा तक बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना डीप डिप्रेशन सोमवार शाम तक दक्षिण और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के मध्यवर्ती हिस्सों में चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है।

आईएमडी ने मंगलवार शाम तक इसके गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान जताया है। इसके और अधिक तीव्र होने तथा अगले दो दिनों में उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश के तट की तरफ जाने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, 17 और 20 नवंबर को उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश तथा कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं, 18 और 19 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इससे तमिलनाडु के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में 18 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है।

छत्तीसगढ़ की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा को राष्ट्रपति भवन में मिला सम्मान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिले कोंडागांव और रायगढ़ के बेलमेटल शिल्पकार

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ की शिल्प परंपरा और पीढ़ियों से संजोए गए हुनर को सोमवार को राष्ट्रपति भवन में विशेष पहचान मिली। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने प्रदेश के कोंडागांव और रायगढ़ से पहुंचे 50 बेलमेटल शिल्पकारों से मुलाकात की। पारंपरिक बेलमेटल शिल्पकला को जीवंत बनाए रखने वाले इन कलाकारों के लिए यह एक गौरवपूर्ण अवसर रहा। राष्ट्रपति भवन में हुई इस विशेष मुलाकात ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक कारीगरी और शिल्पकारों की पीढ़ियों की साधना को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत और सचिव राजेश सिंह राणा भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कोंडागांव एवं रायगढ़ के बेलमेटल शिल्पकारों से भेंट करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसी क्रम में शिल्पकारों का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली पहुंचा और राष्ट्रपति से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ की बेलमेटल कला, विशेष रूप से बस्तर की प्रसिद्ध ढोकरा शिल्प परंपरा, अपनी विशिष्ट निर्माण शैली और बारीक कारीगरी के लिए जानी जाती है। धातु से तैयार देवी-देवताओं, पशु-पक्षियों, लोकजीवन और पारंपरिक आकृतियों में प्रदेश की जनजातीय संस्कृति की गहरी छाप दिखाई देती है। कोंडागांव के शिल्पकार पीढ़ियों से इस कला को संरक्षित करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जीवंत हस्तशिल्प परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण पहल उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति भवन में देश के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को अपनी कला एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने के अवसर मिलते रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के शिल्पकारों की यह मुलाकात प्रदेश की जीवंत हस्तशिल्प परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण पहल है।



छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि और पारंपरिक कारीगरी की विशिष्ट पहचान

यह अवसर उन शिल्पकारों के लिए विशेष महत्व रखता है, जो पीढ़ियों से प्राप्त पारंपरिक ज्ञान, कौशल और कलात्मक विरासत को आज भी जीवंत बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति भवन तक उनकी पहुंच छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि और पारंपरिक कारीगरी की विशिष्ट पहचान को रेखांकित करती है।

स्कूली बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलते नजर आए प्रिंस विलियम

मुंबई। ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स विलियम और प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन ने मुंबई के बॉलार्ड एस्टेट में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की। इस दौरान तीनों के बीच क्रिकेट को लेकर दिलचस्प बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान शाही जोड़े ने एक विशेष रूप से लगाए गए चाय के स्टॉल पर पारंपरिक कुल्हड़ में चाय का भी आनंद लिया। इसके बाद उन्होंने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बॉलार्ड एस्टेट में स्कूल के बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का कार्यक्रम भी रखा गया था। वायरल वीडियो में प्रिंस विलियम बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते दिख रहे हैं।



जशपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने जशपुर प्रवास के दौरान कुनकुरी में लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ के पावन अवसर पर उगते सूर्य को अर्ध्य देकर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

मनीला पहुंचे मोदी एयरपोर्ट पर स्वागत

मनीला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को फिलीपींस के तीन दिवसीय दौरे पर मनीला पहुंचे। इस दौरान मनीला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फिलीपींस के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी के स्वागत में कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पीएम मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय व वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करना है। पीएम मंगलवार को 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वह फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर वहां पहुंचे हैं। मनीला रवाना होने से पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आसियान देशों के साथ भारत के संबंध उसकी एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में हैं और महासागर विजन में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। महासागर का पूरा नाम म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन है। इसका अर्थ विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति है।

कुलगाम में लतीफ भट समेत 2 आतंकी मारे जाने की सूचना

नई दिल्ली। सोमवार को कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकी के मारे जाने की सूचना है। इनमें लश्कर का टॉप कमांडर आतंकी लतीफ भट भी शामिल है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है। लतीफ भट पर बुधवार को कुलगाम में सीआरपीएफ के सुरक्षा ठिकाने पर हुए हमले में शामिल होने का शक था। कुलगाम जिले में सीआरपीएफ की टीम पर हुए हमले के बाद सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। कुलगाम जिले में बुधवार दोपहर करीब सवा दो बजे दो आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से सीआरपीएफ के नाके पर हमला कर दिया। हमले में तीन जवान घायल हो गए थे। वारदात कुलगाम के नौपोरा अखरन इलाके की है। यह स्थान श्रीनगर से लगभग 75 किलोमीटर दूर और कड़ी सुरक्षा वाले जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से बमुश्किल एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूत्रों ने बताया कि सीआरपीएफ की 46वीं बटालियन का दल नौपोरा अखरन इलाके में नियमित ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान पैदल पहुंचे दो आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।

कंबल का फंदा बनाकर महासमुंद जिला जेल से 4 कैदी फरार

महासमुंद। महासमुंद जिला जेल से चार विचाराधीन बंदी फरार हो गए। घटना सोमवार तड़के करीब 4 बजे की बताई जा रही है। बंदियों ने कंबलों को आपस में बांधकर फंदा बनाया और जेल की दीवार फांदकर बाहर निकलने में कामयाब रहे। घटना सामने आते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। फरार बंदियों की तलाश में पुलिस और जेल प्रशासन की टीमें जुट गई हैं।॥ जानकारी के अनुसार, फरार हुए चार बंदियों में दो जबलपुर (मध्यप्रदेश), एक राजस्थान और एक महासमुंद जिले का निवासी है। चारों अलग-अलग आपराधिक मामलों में विचाराधीन बंदी के रूप में जेल में बंद थे। इनमें तीन पर गांजा तस्करी और एक पर चोरी का आरोप है। बताया जा रहा है कि सोमवार तड़के बंदियों ने सुनियोजित तरीके से फरार होने की कोशिश की।



तालाब गायब, अब एनजीटी ने मांगा हिसाब

अलीगढ़। अलीगढ़ जिले में कभी करीब 12 हजार तालाब और दूसरे जलस्रोत होने का दावा किया गया है, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 400 से 450 रह जाने की बात सामने आई है। जलस्रोतों के गायब होने और भूजल स्तर गिरने के इस मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने संज्ञान लिया है। अधिकरण ने जिलाधिकारी अलीगढ़ समेत चार सरकारी एजेंसियों की संयुक्त समिति गठित कर जलस्रोतों की वास्तविक स्थिति की जांच करने और पर्यावरणीय उल्लंघन मिलने पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। समिति को तीन महीने में रिपोर्ट देनी होगी। यह मामला डॉ. एम. सलाहुद्दीन की ओर से एनजीटी को भेजी गई शिकायत से सामने आया है। शिकायत में कहा गया है कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 1960-65 के दौरान अलीगढ़ जिले में अलग-अलग आकार के करीब 12 हजार जलस्रोत थे। अब इनमें से केवल 400 से 450 ही बचे हैं। इनमें भी कई सूख चुके हैं या गायब हो गए हैं। याचिकाकर्ता ने जलस्रोतों के खत्म होने को भूजल स्तर गिरने की प्रमुख वजह बताया है। एनजीटी ने 16 नवंबर को सुनवाई के बाद मामले में तथ्यात्मक स्थिति की जांच जरूरी मानी।

मिशनरी स्कूलों को शमिक भट्टाचार्य की चेतावनी

कोलकाता। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने ईसाई मिशनरी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ शिक्षण संस्थानों में भारतीय संस्कृति और भगवा रंग के प्रति विरोध का माहौल बनाया जा रहा है। साथ ही, कोलकाता के एक मिशनरी स्कूल के भीतर पाकिस्तानी झंडा रखे जाने और एक प्रतिष्ठित ईसाई कालेज के प्राचार्य द्वारा आसनसोल-बर्द्धमान क्षेत्र में हिंदुओं के मतांतरण की गतिविधियों में शामिल होने का उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की गतिविधियों को राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

शमिक ने कहा कि ईसाई समुदाय और मिशनरी संस्थानों को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसके नाम पर भारतीय संस्कृति और भगवा रंग का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत में अब ब्रिटिश शासन नहीं है और बंगाल में स्वतंत्र सरकार है।

शमिक ने आरोप लगाया कि कोलकाता के एक मिशनरी स्कूल के अधिकारी ने परिसर में पाकिस्तानी झंडा रखा है। ऐसे लोगों को अपनी कार्यशैली में सुधार करना चाहिए।

पत्रकारिता, नैतिकता और लोकतंत्र की परीक्षा

योगेश कुमार गोयल

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखने तथा उसका सम्मान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष 16 नवम्बर को 'राष्ट्रीय प्रेस दिवस' मनाया जाता है। वास्तव में यह दिवस एक वैधानिक और अर्ध-न्यायिक प्रतिष्ठान के रूप में भारतीय प्रेस परिषद को स्वीकार करने तथा सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जो देश में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। पत्रकारिता की नैतिकता और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत में प्रथम प्रेस आयोग ने 1956 में एक समिति की कल्पना की थी और 10 वर्ष बाद 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की, जिसने 16 नवम्बर 1966 को अपना कार्य शुरू किया। उसी के बाद से प्रतिवर्ष 16 नवम्बर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय प्रेस परिषद देश में स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अलावा विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए एक नैतिक प्रहरी के रूप में सभी पत्रकारिता गतिविधियों की निगरानी करती है तथा यह भी सुनिश्चित करती है कि देश में प्रेस किसी बाहरी मामले से प्रभावित न हो। राष्ट्रीय प्रेस दिवस वास्तव में प्रेस की स्वतंत्रता तथा समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का प्रतीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार से देश में प्रेस की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित होती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जहां प्रेस ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, वहीं स्वतंत्रता के बाद भी अनेक अवसरों पर सिद्ध होता रहा है कि प्रेस के बिना भारतीय लोकतंत्र अधूरा है। पत्रकार को समाज का ऐसा आईना माना जाता रहा है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई को सामने लाता है। भारत में प्रेस को जनता की एक ऐसी 'संसद' की उपाधि दी गई है, जिसका कभी सत्रावसान नहीं होता और जो सदैव जनता के लिए कार्य करती है। इसे समाज में परिवर्तन लाने अथवा जागृत करने के लिए जन-संचार का एक सशक्त माध्यम माना गया है। प्रेस को समाज की चिंतन प्रक्रिया का एक ऐसा अनिवार्य तत्व माना गया है, जो उसे दिशा व गति देने में सक्षम हो। इसे जनता की ऐसी आंख माना गया है, जो सभी पर अपनी पैनी और निष्पक्ष दृष्टि रखे। प्रेस को जनता की उंगली माना गया है, जो गलत कार्यों के विरोध में स्वत: ही उठ जाती है। प्रेस को समाज के प्रति पूर्ण समर्पण के रूप में देखा जाता है। इसे केवल एक पेशा न मानकर जनसेवा का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है।

प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को दुनिया की कई महान् हस्तियों ने अपने-अपने शब्दों में रेखांकित किया है। पूर्व राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा के शब्दों में कहें तो प्रेस पर लोकतांत्रिक परम्पराओं की रक्षा करने और शांति व भाईचारा बढ़ाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रेस की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रेस का प्रथम उद्देश्य जनता की इच्छाओं और विचारों को समझना तथा उन्हें सही ढ़ंग से व्यक्त करना है जबकि दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भयतापूर्वक प्रकट करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के मुताबिक हमारी स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, जिसे खोये बिना सीमित नहीं किया जा सकता। अमेरिका के जाने-माने समाचार प्रस्तोता और विख्यात पत्रकार वाल्टर क्रोनकाइट का कहना था कि प्रेस की स्वतंत्रता केवल लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह लोकतंत्र है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी कहते थे कि एक राष्ट्र, जो अपने लोगों को एक खुले बाजार में सच्चाई और झूठ का न्याय करने से डरता है, वह एक ऐसा राष्ट्र है, जो अपने लोगों से डरता है। ब्रितानी कंजर्वेटिव पार्टी के राजनेता, लेखक तथा दो बार प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन डिसरायली का कहना था कि प्रेस न केवल स्वतंत्र है बल्कि शक्तिशाली भी है और वह शक्ति हमारी है। नेल्सन मंडेला ने भी एक स्वतंत्र प्रेस को लोकतंत्र के स्तंभों में से एक बताया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रेस की स्वतंत्रता को एक ऐसा अनमोल विशेषाधिकार बताया था, जिसे कोई भी देश नहीं छोड़ सकता। प्रेस से जुड़े लोगों के कंधों पर समाज में स्वस्थ मानक स्थापित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और चूंकि प्रेस को समाज का दर्पण माना गया है, अत: उस दर्पण में हम जनता को जो कुछ दिखाएंगे, वही उसे नजर आएगा। इसलिए प्रेस जगत के लोगों से समाज के हर वर्ग को यही उम्मीद होती है कि उनका चरित्र अच्छा हो, उनके लेखन में निष्पक्षता और पारदर्शिता हो तथा वे ऊंचे आचार सिद्धांतों को अपनाएं।



कबरा हाथी का दहशत: 20 स्कूलों में दी गई छुट्टी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में इन दिनों कबरा हाथी की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उदयपुर क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए एहतियातन करीब 20 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। स्कूलों में आगामी आदेश तक छुट्टी घोषित की गई है। जानकारी के अनुसार, 18 हाथियों का दल तेंदुटिकरा और सरमा जंगल के बीच विचरण कर रहा है। हाथियों की लगातार मौजूदगी से आसपास के गांवों में खतरा बना हुआ है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। इधर, वन विभाग का अमला हाथियों की निगरानी में जुटा हुआ है। वनकर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हाथियों के दल को पहाड़ी इलाकों की ओर जाने से रोका जा सके। इसके लिए वन विभाग की टीम तमाम उपाय कर रही है। वहीं, कबरा हाथी को ट्रेंकुलाइज करने का प्रयास लगातार चौथे दिन भी जारी है, लेकिन अब तक वन विभाग को सफलता नहीं मिल पाई है। लगातार कोशिशों के बावजूद कबरा हाथी को काबू में नहीं किया जा सका है। ऐसे में क्षेत्र में वन विभाग की टीम अलर्ट पर है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।

4 वाहनों में क्कसे आ रहा था छत्तीसगढ़, घेराबंदी कर पकड़ा



बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होते ही अवैध धान के कारोबार पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बलरामपुर जिले में धान की कालाबाजारी और अवैध परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक टीम ने चार पिकअप वाहनों से 255 बोरी अवैध धान जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को भी पकड़ा है, जबकि पिकअप चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक, एसडीएम आनंद राम नेताम के नेतृत्व में प्रशासन और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने सनावल थाना क्षेत्र के ठुल्लू पत्थर में घेराबंदी कर यह कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि ग्रामीण रास्तों के जरिए उत्तर प्रदेश से अवैध धान छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था। इसी दौरान टीम ने चार पिकअप वाहनों को रोककर जांच की, जिसमें 255 बोरी धान लोड मिला। कार्रवाई के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को टीम ने पकड़ लिया। वहीं, पिकअप चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पकड़े गए व्यक्ति से एसडीएम ने घटनास्थल पर ही पूछताछ की। इस कार्रवाई की खास बात यह रही कि एसडीएम आनंद राम नेताम ने स्वयं करीब 30 किलोमीटर तक पिकअप चलाकर जब्त वाहनों को सनावल पुलिस के सुपुर्द किया। गौरतलब है कि जिले में धान खरीदी शुरू होने के साथ ही बिचौलिए और अवैध धान कारोबार से जुड़े लोग सक्रिय हो गए हैं। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है।

कुनकुरी में सीएम विष्णुदेव साय ने मनाया छठ

उगते सूर्य को दिया अर्घ्य, 23.17 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन



जशपुरनगर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छठ महापर्व के अवसर पर कुनकुरी के छठ घाट पहुंचकर अपनी धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ उगते सूर्य देव को उषा अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और जनकल्याण की कामना की।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को छठ पूजा की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में छठ महापर्व के प्रति लोगों की गहरी आस्था और श्रद्धा है। उन्होंने कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में छठ महापर्व के इस पावन अवसर पर शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। छठ पूजा लोक आस्था, श्रद्धा और समर्पण का अनुपम पर्व है, जो हमें प्रकृति, जल और सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रेरणा देता है।

छठ महापर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुनकुरी नगरवासियों को 23 करोड़ 17 लाख रुपये के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देते हुए उनका भूमिपूजन किया। इन विकास कार्यों में छठ तालाब का विस्तार एवं चौड़ीकरण, तालाब का रिज्युविनेशन, मल्टीपर्पस हॉल एवं सांस्कृतिक भवन, सड़क निर्माण और जिम निर्माण शामिल हैं। छठ तालाब के विकास एवं चौड़ीकरण के लिए 5 करोड़ 17 लाख रुपये तथा तालाब के रिज्युविनेशन कार्य के लिए 6 करोड़ 89 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह मल्टीपर्पस हॉल एवं सांस्कृतिक भवन का निर्माण लगभग 3 करोड़ 11 लाख रुपये की लागत से कराया जाएगा।इसके अलावा कुनकुरी छठ तालाब से बंदरा खसरा नाला तक सड़क निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपये और जिम निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन विकास कार्यों के पूरा होने से कुनकुरी में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। छठ तालाब के विकास और चौड़ीकरण से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, वहीं रिज्युविनेशन कार्य से तालाब के संरक्षण एवं सुधार में मदद मिलेगी। मल्टीपर्पस हॉल एवं सांस्कृतिक भवन बनने से सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक आयोजनों के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध होगा। सड़क निर्माण से आवागमन सुगम होगा, जबकि जिम बनने से युवाओं को व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों के लिए सुविधा मिलेगी।छठ महापर्व भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना का चार दिवसीय पर्व है।इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है। दूसरे दिन खरना पर व्रती उपवास रखकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है, जबकि चौथे दिन उगते सूर्य को उषा अर्घ्य अर्पित कर व्रत का समापन किया जाता है। यह पर्व पवित्रता, अनुशासन, त्याग और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का संदेश देता है।

बस्तर से अब सुरक्षाबलों की वापसी शुरू





कवर्धा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान में मिली सफलता के बाद अब बस्तर में तैनात सुरक्षाबलों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहे बस्तर संभाग में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी ष्टत्रक्कत्र के जवान तैनात हैं। लेकिन अब उन्हें दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। इसकी जानकारी डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी।

जानकारी के मुताबिक, बस्तर में तैनात एक हजार से अधिक जवानों को मणिपुर भेजने की तैयारी है। वहीं, आने वाले एक महीने के भीतर कुछ और बटालियनों को भी बस्तर से वापस बुलाया जा सकता है। दरअसल, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों ने लगातार अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। इसके बाद बस्तर में सुरक्षाबलों की तैनाती की जरूरत और मौजूदा परिस्थितियों की समीक्षा की जा रही है।इस पूरे मामले पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब इन बलों की पहले जैसी आवश्यकता नहीं रह गई है। परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षाबलों को दूसरे स्थानों पर भेजा जा रहा है।नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में मिली सफलता के बाद बस्तर से केंद्रीय बलों की वापसी को प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के बदलते हालात के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, बस्तर में स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती के जरिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी बनी रहेगी।

बेमेतरा की डेयरी में छापा, 900 किलो नकली पनीर 2000 किलो खोवा जब्त



बेमेतरा। बेरला शहर के लिमाही चौक स्थित उत्सव डेयरी में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। स्टेट विजिलेंस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने डेयरी में देर शाम दबिश देकर भारी मात्रा में पनीर बरामद किया। मौके पर अस्वच्छ हालत में पाये जाने के कारण 900 किलो किलो पनीर, 2 हजार किलो खोवा जब्त कर नष्ट कराया गया गया है।सैंपल जांच के लिए रायपुर भेजा गया है। विभाग ने डेयरी को सील कर दिया है। बेमेतरा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेरला के लिमाही चौक स्थित उत्सव डेयरी को लेकर आसपास के रहवासियों ने गंदगी और तेज दुर्गंध की शिकायत की थी। लोगों का आरोप था कि डेयरी से निकलने वाले गंदे पानी और बदबू के कारण आसपास के क्षेत्र में रहना मुश्किल हो रहा है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभागीय टीम ने डेयरी पहुंचकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान स्टेट विजिलेंस टीम के डोमेन ध्रुव, खाद्य एवं औषधि विभाग के आशीष कुमार यादव और बेमेतरा खाद्य एवं औषधि विभाग के राजू कुर्रे सहित अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर नगर पंचायत और बेरला की पुलिस विभाग की टीम भी तैनात रही। बेरला के उत्सव डेयरी के संदर्भ में रहवासियों ने शिकायत की थी। साफ सफाई के अभाव में बड़ी तादात में पनीर खोवा जब्त किया गया हैं, 27 अक्टूबर को दीपावली त्यौहार के मद्देनजर विभाग के द्वारा बेरला स्थित उत्सव डेयरी पर औचक निरीक्षण के दौरान अमानक पाए गए लगभग 150 लीटर दूध को मौके पर नियमानुसार नष्ट कराया गया।

10 हजार की लालच में साइबर ठगों को दिया खाता, पहुंच गया सलाखों के पीछे



कवर्धा पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है

कवर्धा। छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी का जाल फैलता जा रहा है। ताजा मामला कवर्धा का है। यहां साइबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध कराने के केस में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने महज 10 हजार रुपये के लालच में अपना बैंक खाता दोस्त को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया था। जांच में उसके बैंक खाते के माध्यम से विभिन्न राज्यों के 14 साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया गया था। उसके खाते से कुल 6 लाख 64 हजार 322 रुपये के लेनदेन का खुलासा हुआ।

कवर्धा पुलिस ने इस केस में जानकारी मीडिया को दी है। पुलिस ने बताया कि समन्वय पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। थाना पिपरिया क्षेत्र के शिव प्रकाश चंद्रवंशी के बैंक खाते में साइबर ठगी की रकम के लेनदेन की जानकारी सामने आई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के निर्देश पर थाना पिपरिया और साइबर पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। पुलिस ने अपराध क्रमांक 389/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(4) और 318(2) में केस दर्ज किया। उसके बाद शिव प्रकाश चंद्रवंशी से पूछताछ की।

कबीरधाम पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि पैसों या कमीशन के लालच में किसी को भी अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक या बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी न दें। ऐसे खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम के लेनदेन में किया जा सकता है। इस वजह से खाताधारक भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं

जीपीएम में राज्य स्तरीय जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का समापन



गौरेला पेंड्रा मरवाही। फिजिकल कॉलेज मैदान पेंड्रा में आयोजित तीन दिवसीय 26वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का शानदार समापन हुआ। प्रतियोगिता में प्रदेश के 26 जिलों की टीमों के कुल 364 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी खेल प्रतिभा, फुर्ती और दमखम का प्रदर्शन किया। अंतिम दिन खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में राजनांदगांव की टीम ने बिलासपुर को हराकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। बिलासपुर उपविजेता रही, जबकि मेजबान गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले ने तीसरा और रायपुर ने चौथा स्थान हासिल किया। समापन समारोह में कलेक्टर विजय दयाराम के। ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले को राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिलना गौरव की बात है। खेल केवल जीत और हार तक सीमित नहीं होते, बल्कि अनुशासन, टीम भावना, आपसी समन्वय और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की सीख भी देते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास और मेहनत से अपनी प्रतिभा निखारने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सफल आयोजन के लिए जिला कबड्डी संघ और आयोजन समिति की सराहना की। जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष एवं नगर पालिका पेंड्रा के अध्यक्ष राकेश जालान ने कहा कि जीत और हार खेल के दो पहलू हैं। हारने वाली टीमों को निराश होने के बजाय उससे सीख लेकर भविष्य की जीत के लिए प्रयास करना चाहिए।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

4 ठिकानों पर रेड मारकर 1000 क्विंटल धान जब्त

धमतरी। प्रदेश में धान खरीदी शुरू होते ही बिचौलिए भी एक्टिव हैं। समर्थन मूल्य का अवैध लाभ उठाने के लिए ये बिचौलिए चोरी छिपे धान जमा कर रहे थे और उसे सरकारी खरीदी केंद्रों में खपाने की फिराक में थे, लेकिन इस बार प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। धमतरी में पिछले दो दिनों से लगातार छापेमारी चल रही है। अवैध धान सिंडिकेट पर बड़ा एक्शन हुआ है। धमतरी जिले में प्रशासन ने 4 अलग अलग जगहों पर एक साथ रेड मारका एक हजार क्विंटल धान जब्त किया है। घुटकेल, उमरगांव, सांकरा और सिंगपुर इन चारों गांवों में अवैध रूप से संग्रहित धान पकड़ा है। कुल करीब 1000 क्विंटल अवैध धान जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3.5 लाख रुपये बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये धान बिना किसी वैध दस्तावेज के जमा किया गया था। ना मंडी लाइसेंस था ना खरीदी का रिकॉर्ड, सिर्फ एक ही मकसद था इस धान को समर्थन मूल्य पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाना। प्रशासन ने मौके पर ही धान को जब्त कर लिया और दोषियों के खिलाफ दण्डात्मक प्रकरण तैयार किया है।

रिटार्यड सरकारी कर्मचारी को दिए अतिरिक्त वेतन वापस ले सकते हैं- एचसी

बिलासपुर। हाईकोर्ट बिलासपुर ने कहा है कि वेतन निर्धारण में गलती के कारण सरकारी कर्मचारी को किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद भी की जा सकती है। हालांकि, असाधारण आर्थिक कठिनाई की स्थिति में राहत मिल सकती है, लेकिन इसके लिए कर्मचारी को अपनी कठिनाई का दावा करने के साथ उसे साक्ष्यों से साबित भी करना होगा। जस्टिस बिभु दत्त गुरु ने उच्च शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त लेखाकार उमेश पाठक की याचिका खारिज करते हुए उनके सेवानिवृत्ति लाभों से अतिरिक्त भुगतान 1 लाख 56 हजार,865 रुपये की वसूली का आदेश बरकरार रखा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सुनवाई का अवसर नहीं देने के कारण पहले वसूली आदेश को रद्द किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि विभाग दोबारा वसूली का आदेश नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि कानूनी अधिकार के बिना किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जा सकती है।

लापता महिला का मिला कंकाल, शोक का माहौल

खैरागढ़। जिले के ग्राम गातापार में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पिछले करीब 15 दिनों से लापता 70 वर्षीय अनुसूईया बाई मंडावी का कंकाल रविवार को धान के खेत में बरामद हुआ। महिला के अवशेष मिलने की खबर फैलते ही गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने तेंदुए के हमले में महिला की मौत होने की आशंका जताई है। परिजनों के मुताबिक, अनुसूईया बाई मंडावी करीब 15 दिनों से लापता थी। आसपास और गांव में पूछताछ करने के बाद भी महिला का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। महिला की तलाश में परिजनों के साथ ग्रामीणों ने भी काफी मशक्कत की। जंगल से लेकर आसपास के गांवों और खेतों तक खोजबीन की गई। ग्रामीणों के मुताबिक तलाश अभियान चलाया गया, लेकिन महिला का कोई पता नहीं चला। आखिरकार रविवार को धान के खेत में उनके कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की मौत को लेकर ग्रामीणों ने तेंदुए के हमले की आशंका जताई है।

गरियाबंद में रेत खदानों में नियमों की उड़ रही धज्जियां

गरियाबंद। जिले में रेत खनन को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कहीं रात के अंधेरे में रेत खदान का भूमिपूजन कर खनन और परिवहन शुरू करने का मामला सामने आया है, तो कहीं नदियों में नियमों को ताक पर रखकर रेत निकाले जाने के आरोप लग रहे हैं। इन मामलों में खनिज विभाग पर मिलीभगत के आरोप लगे हैं। पांडुका थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरकड़ा में रात के अंधेरे में रेत खदान का भूमिपूजन किए जाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में कुछ लोग रात के समय खदान स्थल पर पूजा-पाठ करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि भूमिपूजन के साथ ही मशीन से रेत खनन और परिवहन भी शुरू कर दिया गया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई हैं। जानकारी के मुताबिक, पांडुका क्षेत्र के रसूखदार ने खदान पट्टेदार से सरकड़ा रेत खदान लीज पर ली है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रीतम सिन्हा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि रेत खदान का आवंटन शासन के निर्धारित नियमों एवं पारदर्शी प्रक्रिया के तहत विधिवत किया गया है।

अधेड़ की संदिग्ध मौत पर बवाल हिरासत में महिला दुकानदार

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में एक शख्स की मौत पर बवाल हुआ है. शहर के मिनीमाता चौक में एक अधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद ऐसा हुआ है. मृतक के परिजनों ने एक महिला दुकानदार पर मारपीट कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. घटना से गुस्साए परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में कवर्धा कोतवाली थाना पहुंच गए. लोगों ने महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए बवाल काटा. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम रेंगाखार निवासी शिवकुमार वाचकर किसी काम से कवर्धा आया हुआ था. इसी दौरान मिनीमाता चौक स्थित एक महिला की दुकान पर सामान खरीदने के दौरान किसी बात को लेकर उसका महिला से विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया. परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान महिला ने प्लास्टिक की कुर्सी उठाकर शिवकुमार पर हमला कर दिया. घटना के कुछ देर बाद दिनेश अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. आनन-फानन शख्स को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

महासमुंद जिला जेल से दिवारी कुदकर भाग गए 4 बंदी

विचाराधीन बंदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है



महासमुंद। जिला जेल महासमुंद की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक उजागर हुई है। जेल से 4 विचाराधीन बंदी दीवार कूदकर फरार हो गए हैं। जेल की ऊंची दीवार कैदी कैसे फांद गए इस बात की भी जांच की जा रही है। चार कैदियों के एक साथ फरार हो जाने से जेल प्रबंधन सकते में है। आनन फानन में मामले की रिपोर्ट पुलिस को दी गई है।

जेल प्रबंधन से मिली जानकारी के बाद पुलिस की टीमें लगातार बंदियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। बंदियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें डॉक स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीमों की भी मदद ले रही है। लेकिन अभी तक कोई भी बंदी पकड़ा नहीं जा सका है। कोतवाली पुलिस लगातार मुखबिरों के जरिए बंदियों की पतासाजी करने में जुटी है। बंदी जेल की ऊंची दीवार फांदकर कैसे फरार हो गए इस बात को लेकर हड़कंप की स्थिति है। पता लगाया जा रहा है कि बंदियों को भागने में किसी ने मदद तो नहीं की। शक जताया जा रहा है कि चारों बंदी आज सुबह 3 से 4 बजे के बीच जेलकी पिछली ओर बने दीवार को फांदकर फरार हुए हैं। सुबह जब चारों बंदियों की हाजरी नहीं हुई और साथी बंदियों ने उनको नहीं देखा तो पता चला कि चारों फरार हो चुके हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए जेल के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। पुलिस डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। डॉग स्क्वाड की मदद से जेल के आसपास के इलाकों में लगातार सर्चिंग की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि फरार बंदी जेल से निकलने के बाद किस दिशा में जा सकते हैं। घटनास्थल से संभावित साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, ताकि फरारी के तरीके और उनके भागने के रास्ते का पता लगाया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात चोरी के आरोप में जेल में बंद पंचराम को लेकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पंचराम आदतन बदमाश है और इससे पहले भी जांजगीर-चांपा जिला जेल से फरार होने में कामयाब रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि पूर्व में जेल से फरार होने का इतिहास रखने वाले बंदी को किस तरह की निगरानी की जा रही थी। क्या जेल प्रशासन को उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और फरारी की जानकारी नहीं थी।

अबूझमाड़ के प्रवेश द्वार नारायणपुर में भी छठ की रौनक



नारायणपुर। आदिवासी बहुल नारायणपुर जिले में भी लोक आस्था के महापर्व छठ की भव्य रौनक देखने को मिली। पूर्वांचल के इस प्रमुख त्योहार ने नारायणपुर के बंधुवा तालाब महादेव घाट को उत्तर भारत के घाटों जैसी आस्था और उत्साह से सराबोर कर दिया। 35 वर्षों से जिला भोजपुर समाज इस पर्व को मना रहा है जहां न केवल उत्तर भारत से आए लोग, बल्कि स्थानीय जनजाति समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। 15 नवंबर की शाम, व्रतियों ने छठ व्रत के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया, इसके बाद चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का समापन हुआ। यह प्रकृति की पूजा, खास तौर पर सूर्य देव और छठी मइया की उपासना का पर्व है। यह व्रत संतान के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। यह त्योहार अपने आप में सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन चुका है। नारायणपुर जैसे नक्सल प्रभावित रहे और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में छठ का जनसैलाब भारत की अनेकता में एकता का का प्रमाण है। आयोजन समिति के सदस्यों के अनुसार, स्थानीय जनजाति समाज के लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी ने इसे एक सामुदायिक उत्सव बना दिया है। उत्तर से खाने-कमाने आए छठ व्रतियों के लिए यह महापर्व अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर भी %अपना सा माहौल% महसूस कराता है। नारायणपुर में बंधुवा तालाब महादेव घाट को खूबसूरत तरीके से सजाया गया और डीजे पर बजते छठ महापर्व के गीतों की धुन ने समा बांधे रखा।गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष छठ घाट (महादेव मंदिर घाट) पर नगरपालिका ने खास इंतजाम किए थे। पीने के पानी की व्यवस्था सहित पूरे घाट में साफ सफाई एवं तालाब के जल कुंभी की सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था।

संक्षिप्त समाचार

सुखदेव भगत के छत्तीसगढ़ दौरे पर अजय चंद्राकर ने कसा तंज

रायपुर। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान के तहत तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 'वोट चोरी, वोट बचाओ' संवैधानिक संस्थाओं पर एक आरोप है। असल में 'वोट चोरी, वोट बचाओ' अभियान को 'कांग्रेस बचाओ' अभियान कर देना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के पास अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कोई जनहित विषय नहीं है। सुखदेव भगत की राजनीतिक योग्यता के अनुसार झारखंड में कांग्रेस सत्ता से कितने दिनों से बाहर है, यह भी बताए। वहीं जनजाति गौरव दिवस पर नितिन नबीन के नहीं आने पर कांग्रेस के भाजपा पर जनता का डर का आरोप लगाए जाने पर अजय चंद्राकर ने कहा कि ये कांग्रेस का कार्यालय मौसम विभाग का कार्यालय है क्या? कांग्रेस के नेताओं को मौसम विभाग में संविदा में लगा देना चाहिए। मौसम की उचित जानकारी इन्हें पता है। हकीकत यह है कि मौसम खराब होने की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए। छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ के नक्सल विरोधी बटालियन को हटाए जाने पर पूर्व मंत्री ने कहा कि बस्तर में अब डीमाइनिंग का काम बाकी है। शांति की बहाली हो गई, अब बटालियन वापस हो रही है। नेताओं की सुरक्षा भी घटाई गई है। स्थिति में सुधार आने के कारण क्रमश: ऐसा हो रहा है। बस्तर में विकास का काम अब लक्ष्य होगा।

देवउठनी एकादशी से फिर गूंजेंगी विवाह की शहनाइयां

रायपुर। चार माह के लंबे अंतराल के बाद अब 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी से विवाह की शहनाइयां फिर गूंजेंगी। 2026 में 12 दिसंबर तक मुहूर्त रहेंगे। हालांकि 20 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच मात्र 23 दिनों में कुल 16 दिन विवाह मुहूर्त रहेंगे। 15 दिसंबर से खरमास शुरू होने से एक माह शादियों पर ब्रेक रहेगा। इसके बाद विवाह मुहूर्त 2027 में 18 जनवरी से पुन: शुरू होंगे। नए साल में जनवरी से दिसंबर तक कुल 96 दिन मुहूर्त रहेंगे। ये पिछले 26 साल में सबसे ज्यादा है। इसके पूर्व 2019 में 94 दिन विवाह मुहूर्त थे। जबकि, 2026 में 59 दिन ही मुहूर्त हैं। इसकी वजह यह थी कि जनवरी माह में एक भी विवाह मुहूर्त नहीं था। शुक्र तारा के अस्त रहने के कारण मुहूर्त शुरू ही 5 फरवरी से हुए थे। 2027 में फरवरी माह में सर्वाधिक 17 दिन विवाह की शहनाइयां बजेंगी। 2026 में ये मुहूर्त नवंबर : 20, 21, 24, 25, 26 व 30 कुल 06 दिन दिसंबर : 1 से 6, 9, 10, 11 व 12 कुल 10 दिन (23 दिन में 16 दिन विवाह मुहूर्त) 2027 में 18 जनवरी से 12 जुलाई तक मुहूर्त रहेंगे। इसके बाद 14 जुलाई को देवशयनी एकादशी होने से चातुर्मास शुरू हो जाएगा। इसके बाद मुहूर्त की शुरुआत 20 नवंबर से होगी। इन तिथियों पर सर्वाधिक विवाह 11 फरवरी वसंत पंचमी ज9 मई अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती 12 जुलाई, भड़ली नवमी 3 दिसंबर-विवाह पंचमी।

छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक ऑडिट पखवाड़ा

रायपुर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), रायपुर द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 17 नवंबर से 01 दिसंबर 2026 तक ऑडिट पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान राज्य शासन के विभिन्न विभागों और महालेखाकार कार्यालय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा छत्तीसगढ़ राज्य के लेखों की गुणवत्ता को और उत्कृष्ट बनाने के उद्देश्य से 26 नवंबर को राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला का उद्घाटन वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

ऑडिट पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित यह कार्यशाला 26 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक महालेखाकार आवासीय परिसर, रायपुर स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित होगी। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य की वित्तीय एवं लेखा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना, शासकीय विभागों और महालेखाकार कार्यालय के बीच आपसी समन्वय बढ़ाना तथा राज्य के लेखों की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

पूज्य सिविल लाइंस सिंधी पंचायत का दीपावली मिलन समारोह हर्षोल्लास से सम्पन्न

रायपुर। पूज्य सिविल लाइंस सिंधी पंचायत



द्वारा आयोजित दीपावली मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। समारोह में समाज के सैकड़ों परिवारों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान झूलेलाल साहिब की पूजा-अर्चना एवं दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। भगवान झूलेलाल की आरती महिला विंग अध्यक्ष मधु बहादुर आर्त्तवानी, लक्ष्मी छुगानी, रेनू आहूजा, मीनू रामनानी,रश्मि वाधवा, सोनम नजरानी, निकिता पारवानी,सपना बजाज, महिला टीम के सदस्यों द्वारा की गई। इस अवसर पर पंचायत अध्यक्ष श्री संजय जेसिंध ने स्वागत उद्बोधन देते हुए समाज की एकता एवं बच्चों को शिक्षा और संस्कार से जोड़ने पर जोर दिया। महासचिव श्री मोहन वर्ल्यानी ने सचिवीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए पंचायत की गतिविधियों एवं समाजसेवी कार्यों की जानकारी दी।

विकास के साथ अपनी गौरवशाली विरासत को सहेजना भी हमारी जिम्मेदारी : साय

जनजातीय नायकों का साहस, संघर्ष और बलिदान हमारी राष्ट्रीय चेतना और गौरवशाली इतिहास का अमूल्य हिस्सा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए जनजातीय वीर नायकों का संघर्ष और बलिदान हमारी गौरवशाली विरासत का अमूल्य हिस्सा है। इन महानायकों ने न केवल मातृभूमि की आजादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि अपनी संस्कृति, परंपराओं, स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा के लिए भी अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनका जीवन हमें साहस, एकता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री श्री साय आज बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर श्स्वतंत्रता संघर्ष में जनजातीय नायकों का योगदानश् विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास के साथ अपनी गौरवशाली विरासत को सहेजना और नई पीढ़ी तक पहुँचाना भी हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने जनजातीय वीथिका का अवलोकन कर जनजातीय वीर नायकों के जीवन, संघर्ष और बलिदान पर आधारित



प्रदर्शनी की सराहना की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगोष्ठी की स्मारिका का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री साय ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने मात्र 25 वर्ष के जीवन में अंग्रेजी शासन के अन्याय और शोषण के विरुद्ध ऐतिहासिक संघर्ष किया। जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने जनजातीय समाज को संगठित किया और उलगुलान आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। उनका साहस, स्वाभिमान और बलिदान आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती जनजातीय वीरों के साहस और बलिदान की साक्षी रही है। शहीद वीर नारायण सिंह ने अकाल के समय भूखी जनता की सहायता के लिए संघर्ष किया और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। इसी प्रकार अनेक जनजातीय नायकों ने देश की स्वतंत्रता और समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन महानायकों की गौरवगाथाओं को नई पीढ़ी तक पहुँचाना आवश्यक है, ताकि हमारे युवा अपने इतिहास और संस्कृति पर गर्व कर सकें। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में उसके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की पहल इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उनकी 151वीं जयंती के अवसर पर प्रदेशभर में जनजातीय गौरव सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूलों, महाविद्यालयों और विकासखंड स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को जनजातीय नायकों के जीवन और योगदान से परिचित कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपराएँ और जीवन मूल्य छत्तीसगढ़ की पहचान हैं। हमारी सरकार इन्हें सहेजने के साथ ही जनजातीय परिवारों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लगभग साढ़े छह हजार गाँव शामिल हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बसाहटों तक सड़क, बिजली, रसोई गैस और सौर ऊर्जा जैसी बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाई जा रही हैं। राज्य सरकार ने जनजातीय समाज की परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था को सहेजने वाले मांझी, चालकी और बैगा का मानदेय भी बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का आसीन होना जनजातीय समाज के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और समर्पण से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारी सरकार का प्रयास है कि समाज के युवाओं को आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलें और वे विकसित भारत एवं विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के उत्थान में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के योगदान की सराहना की। उन्होंने स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जूदेव के कार्यों को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने जनजातीय समाज के सम्मान और हितों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। मुख्यमंत्री ने श्री जोगेश्वर यादव की सेवा भावना की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि पहाड़ी कोरवा और बिरहोर समुदाय के बीच श्री यादव ने सेवा और समर्पण से जो विश्वास अर्जित किया है, वह अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री श्री साय ने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा के साथ सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ बटालियन हटाने पर भूपेश बघेल ने कहा

जवानों की वापसी प्रशासनिक व्यवस्था विकास के काम बताए सरकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ की पूरी बटालियन हटाई गई। इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, सीआरपीएफ जवानों की वापसी एक प्रशासनिक व्यवस्था है। सरकार को विकास के काम बताना चाहिए। पंचायतों को एक करोड़ रुपए देने का वादा किया गया था। विकास को बताएं, केवल जमा खाता बताने से कुछ नहीं होगा। जब सामान्य व्यवस्था बहाल हो जाए तब माना जाएगा कि नक्सलवाद खत्म हो चुका है।

धान खरीदी पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मूर्खता की हद हो जाती है। सरकार की नीति यही है कि किसान धान बेच ना पाएं। सरकार यही षड्यंत्र कर रही है। धान खरीदी केंद्रों में टोकन

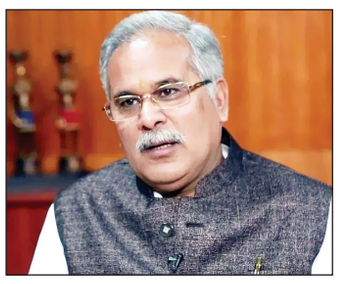

के लिए किसानों को जाना पड़ता था। कांग्रेस सरकार ने धान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ा दी थी।

भाजपा नेता ने कहा, कांग्रेस सरगुजा संभाग को साधने की तैयारी में है। इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, स्मृति ईरानी ने पिछले दिनों फीडबैक लिया। जमीन में कहीं ये लोग निकल नहीं रहे थे। किसान मेहनत करके धान उगाते हैं और भाजपा सरकार किसानों को चोर समझती है।

छग कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत के दौरे पर अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया। इस पर भूपेश बघेल ने कहा, अजय चंद्राकर अचानक कभी कभी प्रकट होते हैं। चंद्राकर केवल विधानसभा तक सीमित है। उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। अजय चंद्राकर कांग्रेस पर बोलकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में नितिन नबीन नहीं पहुंचे। इस मामले में बघेल ने अजय चंद्राकर के बयान पर तंज कसते हुए कहा, अजय चंद्राकर रायगढ़ में हैं या कुरुद के बंगले में आराम फरमा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री रायपुर में थे तो उसी वक्त पर रायगढ़ कैसे पहुंच गए।

राजधानी में फैली गंदगी पर निगम उपायुक्त और जोन आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी

- 3 दिन के भीतर मांगा गया जवाब

रायपुर। राजधानी रायपुर में फैली गंदगी पर नगरीय प्रशासन विभाग ने रायपुर नगर पालिका निगम के दो वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। निगम आयुक्त को जवाब का परीक्षण कर अभिमत सहित संचालनालय को भेजने कहा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से रायपुर निगम उपायुक्त (सफाई प्रभारी) जसदेव बाबरा और जोन क्रमांक-4 की आयुक्त दिव्या चन्द्रवंशी को जारी नोटिस में कहा गया है कि प्रत्येक समीक्षा बैठक में नगर की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया जाता रहा है, किन्तु आपके द्वारा वरिष्ठालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपनी कार्य प्रणाली में आशातीत सुधार नहीं किया गया है।

नोटिस में कहा गया है कि आए दिन समाचार पत्रों में जगह-जगह गंदगी फैले होने संबंधी समाचार प्रकाशित होते हैं, जो नगर निगम एवं शासन की छवि धूमिल करने के साथ-साथ आपकी (रायपुर निगम



उपायुक्त (सफाई प्रभारी) जसदेव बाबरा, जोन क्रमांक-4 आयुक्त दिव्या चन्द्रवंशी) कार्य प्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है।

विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति एवं सेवा के निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2018 के प्रावधानों के तहत जारी नोटिस पर 3 दिनों के भीतर रायपुर नगर निगम के आयुक्त के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। निर्धारित समयावधि में जवाब नहीं दिए जाने पर नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

राजनांदगांव ने जीता राज्य स्तरीय चैंपियनशिप का खिताब

रायपुर। छत्तीसगढ़ की बेटियों ने कबड्डी के मैदान में अपनी प्रतिभा, साहस, फुर्ती और अद्भुत खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन कर यह साबित कर दिया कि खेल के क्षेत्र में भी प्रदेश की बालिकाएं निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हैं। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के फिजिकल कॉलेज मैदान, पेण्ड्रा में आयोजित तीन दिवसीय 26वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का रविवार को उत्साह, उमंग और खेल भावना के साथ भव्य समापन हुआ। प्रतियोगिता के रोमांचक फाइनल मुकाबले में राजनांदगांव की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बिलासपुर को पराजित कर राज्य स्तरीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। बिलासपुर की टीम उपविजेता रही, जबकि मेजबान गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले ने तीसरा तथा रायपुर जिले ने चौथा स्थान प्राप्त किया।

13 से 15 नवंबर तक आयोजित इस प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 26 जिलों की टीमों के कुल 364 बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। तीन दिनों तक चले मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा, शारीरिक क्षमता, रणनीतिक कौशल और सामूहिक समन्वय का उत्कृष्ट परिचय दिया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के जोश



और उत्साह ने दर्शकों को रोमांचित किया। विशेष रूप से अंतिम दिन खेले गए फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली।

प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला राजनांदगांव और बिलासपुर की टीमों के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने खिताब हासिल करने के लिए पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों की फुर्ती, मजबूत रक्षात्मक रणनीति, आक्रामक खेल और आपसी तालमेल ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। राजनांदगांव की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बिलासपुर को पराजित कर विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। बिलासपुर की टीम ने भी उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए उपविजेता का स्थान हासिल किया।

छत्तीसगढ़ की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा को राष्ट्रपति भवन में मिला सम्मान

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिले छत्तीसगढ़ के बेलमेटल शिल्पकार
- कोंडागांव और रायगढ़ के शिल्पकारों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात



रायपुर। छत्तीसगढ़ की शिल्प परंपरा और पीढ़ियों से संजोए गए हुनर को सोमवार को राष्ट्रपति भवन में विशेष पहचान मिली। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने प्रदेश के कोंडागांव और रायगढ़ से पहुंचे 50 बेलमेटल शिल्पकारों से मुलाकात की। पारंपरिक बेलमेटल शिल्पकला को जीवंत बनाए रखने वाले इन कलाकारों के लिए यह एक गौरवपूर्ण अवसर रहा। राष्ट्रपति भवन में हुई इस विशेष मुलाकात ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक कारीगरी और शिल्पकारों की पीढ़ियों की साधना को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत और सचिव श्री राजेश सिंह राणा भी उपस्थित रहे।नक्शे देखें

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कोंडागांव एवं रायगढ़ के बेलमेटल शिल्पकारों से भेंट करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसी क्रम में शिल्पकारों का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली पहुंचा और राष्ट्रपति से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ की बेलमेटल कला, विशेष रूप से बस्तर की प्रसिद्ध ढोकरा शिल्प परंपरा, अपनी विशिष्ट निर्माण शैली और बारीक कारीगरी के लिए जानी जाती है। धातु से तैयार देवी-देवताओं, पशु-पक्षियों, लोकजीवन और पारंपरिक आकृतियों में प्रदेश की जनजातीय संस्कृति की गहरी छाप दिखाई देती है। कोंडागांव के शिल्पकार पीढ़ियों से इस कला को संरक्षित करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं।नक्शे देखें

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति भवन में देश के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को अपनी कला एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने के अवसर मिलते रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के शिल्पकारों की यह मुलाकात प्रदेश की जीवंत हस्तशिल्प परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण पहल है। यह अवसर उन शिल्पकारों के लिए विशेष महत्व रखता है, जो पीढ़ियों से प्राप्त पारंपरिक ज्ञान, कौशल और कलात्मक विरासत को आज भी जीवंत बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति भवन तक उनकी पहुंच छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि और पारंपरिक कारीगरी की विशिष्ट पहचान को रेखांकित करती है

पटवारियों के समर्थन में आए भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, बोले जायज हैं मांगें

रायपुर। पूरे छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। धान खरीदी शुरू हुए 1 दिन बीत चुका है और हड़ताल पर गए पटवारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हड़ताल पर बैठे पटवारियों को अब बीजेपी सरकार के ही विधायक अजय चंद्राकर (कुरूद विधानसभा सीट) का साथ या कहें समर्थन मिला है।

बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने पटवारियों की मांगों को जायज बताते हुए कहा, %%सरकार को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।%% अजय चंद्राकर ने यह भी स्पष्ट किया कि पटवारी संघ की हड़ताल सरकार के गले की फांस नहीं है। सरकार अलग-अलग स्तर पर पटवारी संघ से बातचीत कर रही है और मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने उम्मीद जताई है कि आने वाले कुछ दिनों में इस विवाद का हल निकल जाएगा। वहीं, धान खरीदी को लेकर विधायक ने कहा कि सरकार ने पर्याप्त और पुख्ता व्यवस्था की है और खरीदी में रुकावट आने की कोई सूचना नहीं है।

पटवारी संघ की हड़ताल को लेकर भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर का बयान कई मायनों में अहम है। उन्होंने सीधे तौर पर पटवारियों की मांगों को जायज बताया है। अजय चंद्राकर का कहना है कि सरकार अलग-अलग तरीके से और अलग-अलग स्तर पर पटवारी संघ से बातचीत कर रही है। सरकार की कोशिश है कि सभी संबंधित संस्थाओं और पक्षों को साथ लेकर जनता के हित में काम किया जाए। बीजेपी विधायक ने कहा कि सरकार इस दिशा में प्रतिबद्ध है और मुख्यमंत्री भी समस्या के समाधान को लेकर गंभीर हैं। अजय चंद्राकर ने भरोसा जताया कि कुछ दिनों में इस पूरे मामले का हल निकल सकता है।

बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने पटवारियों की हड़ताल को सरकार के लिए बड़ी परेशानी या गले की फांस मानने से



इनकार किया। विधायक का मानना है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत और आपसी सहमति से ही संभव है। सरकार पटवारी संघ के साथ संवाद कर रही है और सभी पक्षों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है।

बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पटवारी संघ अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है। पटवारी संघ की हड़ताल को खत्म कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सख्ती भी दिखाई जा रही है। ऐसे में भाजपा के वरिष्ठ विधायक का बातचीत और सहानुभूतिपूर्ण विचार पर जोर देना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पटवारियों की हड़ताल के बीच धान खरीदी को लेकर भी अजय चंद्राकर ने सरकार का पक्ष भी रखा। विधायक ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो चुकी है और कहीं भी खरीदी में रुकावट आने की सूचना नहीं है। अजय चंद्राकर के मुताबिक, सरकार ने धान खरीदी के लिए पर्याप्त और पुख्ता इंतजाम किए हैं। विधायक ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि पटवारियों की हड़ताल के बावजूद किसानों से जुड़ी धान खरीदी की व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई। सरकार इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तैयार है।

बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर दोहराया कि पटवारियों की मांगें जायज हैं, सरकार को इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है। उनका बयान ऐसे समय आया है, जब पटवारी संघ वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति, कार्य संबंधी समस्याओं और अन्य लंबित मांगों को लेकर आंदोलन पर है। संघ की मांग है कि सरकार उनकी समस्याओं पर ठोस निर्णय लेकर लिखित आदेश जारी किया जाए।

छत्तीसगढ़ में पटवारी संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सरकार की ओर से कर्मचारियों को काम पर लौटने के निर्देश मिले हैं। सख्ती के तौर पर अलग-अलग जिलों में पटवारियों को नोटिस जारी करने, निलंबन और अन्य विभागीय कार्रवाई भी की गई। इस कार्रवाई को लेकर कर्मचारी संगठनों में और भी नाराजगी बढ़ गई है। दूसरे कर्मचारी संगठन भी पटवारियों के समर्थन में सामने आ रहे हैं। पटवारी संघ का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

लोकसभा का चुनाव वैध या अवैध?

सनत जैन

भारत की राजनीति में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर चल रहा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। अभी तक कांग्रेस और विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलकर एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे। लेकिन अब राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की वैधता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में विदेशी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 2024 का लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और वैध नहीं था। यह आरोप भारतीय लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था के लिए एक गंभीर राजनीतिक चुनौती बनकर सामने आया है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में चुनावी प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर के कथित दुरुपयोग, मतदाताओं की संख्या में बदलाव, मतदान प्रतिशत के आंकड़ों और चुनाव आयोग के सिस्टम के केंद्रीकरण जैसे मुद्दे प्रमाणों के साथ उठाए हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट और सामने आए विभिन्न प्रमाणों का हवाला देते हुए आरोप लगाया। चुनाव से पहले ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता सूची और चुनावी आंकड़ों में हेरफेर की गई थी। उनका दावा है, चुनावी व्यवस्था में बदलाव करके परिणामों को प्रभावित किया गया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र जांच और न्यायिक पुष्टि नही है। भाजपा और चुनाव आयोग की ओर से इन आरोपों पर तथ्यात्मक जवाब देखकर राहुल गांधी के आरोपों का अब सार्वजनिक रूप से खंडन करना होगा। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया, भाजपा ने 2014 के बाद से चुनाव जीतने के लिए अरबों रुपये खर्च किए। एसआईआर के माध्यम से लगभग 14 करोड़ मतदाताओं के मतदान का अधिकार छीन लिया है। सवाल यह है कि यदि मतदाता सूची, मतदान प्रक्रिया और चुनाव परिणामों को लेकर संदेह पैदा होता है, तो लोकतंत्र में जनता का विश्वास कैसे कायम रहेगा? दूसरी ओर, किसी चुनाव को अवैध घोषित करना केवल राजनीतिक आरोप से संभव नहीं है। इसके लिए संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया में ठोस प्रमाण भी आवश्यक हैं। इस पूरे विवाद का दूसरा पहलू देश में बदलता राजनीतिक वातावरण है। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भाजपा के चुनावी प्रदर्शन ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी थी। अब महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बढ़ते कर्ज और रोजमर्रा की आर्थिक परेशानियों ने आम आदमी की चिंताएं बढ़ाई हैं। जिस अच्छे दिन की उम्मीद के साथ जनता ने मोदी जी को समर्थन दिया था, वह उम्मीद और वास्तविक जीवन के अनुभवों के बीच अंतर को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। नोटबंदी, जीएसटी और विभिन्न करों का बोझ भी आम जनता की चर्चा का विषय बन चुका है। पहले प्रधानमंत्री की सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ और उनके प्रति दिखाई देने वाला विश्वास, भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत था। अब विभिन्न मुद्दों पर जनता के आंदोलन और विरोध यह संकेत देते हैं, मतदाता पहले की तुलना में अधिक सवाल पूछ रहा है। जो स्वाभाविक परिवर्तन का संकेत है। राहुल गांधी की राजनीति में पिछले कुछ समय में राजनीतिक तौर पर आक्रामकता और सक्रियता बढ़ी है। वे अब केवल कांग्रेस की राजनीतिक विरासत के सहारे नहीं, बल्कि चुनावी पारदर्शिता, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और आम आदमी के अधिकारों जैसे मुद्दों को लेकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशी मंचों और हाल ही में हैदराबाद की भारत समिट में भारतीय चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाने से यह बहस राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर भी पहुंचने लगी है।

बांग्लादेश को अमेरिका और चीन के हाथों बेच देंगे रहमान

नीरज कुमार दुबे



क्या बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार अपने देश को चीन और अमेरिका के हाथों बेच रही है या गिरवी रख रही है? यह सवाल हम नहीं बल्कि बांग्लादेश के लोग उठा रहे हैं। दरअसल, बांग्लादेश में एक तरफ चीन की सरकारी कंपनी को महंगी ख्ल्ल परियोजना का ठेका देकर देश की ऊर्जा व्यवस्था को लंबे समय के लिए विदेशी कंपनी के हवाले करने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते की शर्तों को लेकर भी विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। बांग्लादेश में असंतोष इस बात को लेकर है कि आखिर सरकार बिना अपने राष्ट्रीय और रणनीतिक हितों का आकलन किए, विदेशी शक्तियों के सामने हर शर्त पर हामी क्यों भर रही है? सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्थिक समझौतों और बड़े-बड़े निवेश के नाम पर बांग्लादेश को चीन और अमेरिका की रणनीतिक गिरफ्त में धकेला जा रहा है?

हम आपको बता दें कि ताजा विवाद की शुरुआत कॉक्स बाजार के महेशखाली इलाके में प्रस्तावित तीसरे फ्लोटिंग ख्ल्ल टर्मिनल से हुई है। 12 नवंबर 2026 को बांग्लादेश सरकार ने चीन की सरकारी कंपनी ष्टद्धद्बठ्ठड्डु ह्वड्डह्लद्बश्ठठ्ठड्डद्य श्वठ्ठद्गह्वद्द4 श्वठ्ठद्दद्बठ्ठद्गद्गह्वद्बठ्ठद् ड्डठ्ठस्र ष्टश्ठठ्ठह्यह्लह्वह्ल्द्बश्ठ ष्टश्वद्बश्वड्डड्ड4 (ष्टह्वश्वश्व) के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस परियोजना के लिए 15 वर्षों में लगभग 12,324 करोड़ टका और 20 वर्षों में करीब 13,161 करोड़ टका भुगतान का प्रस्ताव है।

विवाद की सबसे बड़ी वजह इसकी लागत है। कंपनी ने प्रतिदिन 3.42 लाख डॉलर की रीगैसीफिकेशन फीस प्रस्तावित की है, जो मौजूदा अमेरिकी कंपनी श्व×ष्द्यद्यद्गह्वड्डह्लद्ग श्वठ्ठद्गह्वद्द4 की फीस से लगभग 35 प्रतिशत और स्ख्लद्बद्बद्बह्ल ख्ल्ल की फीस से करीब 37 प्रतिशत ज्यादा है। यानी जिस सेवा के लिए पहले से कम भुगतान किया जा रहा है, उसी सेवा के लिए अब चीन की कंपनी को काफी अधिक रकम देने का सवाल खड़ा हो गया है। यह प्रस्ताव अक्टूबर में लागत की समीक्षा के लिए वापस लिया गया था, लेकिन नवंबर में इसे फिर मंजूरी मिल गई। ऐसे में बांग्लादेश के ऊर्जा क्षेत्र में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर महंगी शर्तों के बावजूद इस समझौते को आगे बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी?

बांग्लादेश में इस फैसले को लेकर ऊर्जा विशेषज्ञों और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े लोगों की आपत्तियां सामने आई हैं। बांग्लादेश की ष्टश्ठठ्ठह्यह्लद्बद्गह्वह्य, ह्यह्यश्ठष्ठड्डह्लद्बश्ठठ्ठ से जुड़े ऊर्जा सलाहकार एम. शमसुल आलम ने सवाल उठाया है कि जब अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के सस्ते प्रस्ताव मौजूद थे, तब महंगी पेशकश को आगे बढ़ाने का आधार क्या था? देखा जाये तो यह केवल एक कारोबारी सौदा नहीं है। ख्ल्ल जैसी बुनियादी ऊर्जा व्यवस्था में किसी विदेशी कंपनी के साथ 15 से 20 साल का समझौता देश को लंबे समय तक एक खास तकनीकी और आर्थिक व्यवस्था से बांध सकता है।

साथ ही बांग्लादेश की परेशानी केवल चीन तक सीमित नहीं है। अमेरिका के साथ फरवरी 2026 में हुआ व्यापार समझौता भी देश के भीतर भारी राजनीतिक विवाद का विषय बन चुका है। इस समझौते के खिलाफ ढाका में प्रदर्शन हुए हैं। वामपंथी संगठनों, नागरिक अधिकार समूहों और अर्थशास्त्रियों ने इसे असमान समझौता बताते हुए रद्द करने की मांग की है। आलोचकों की आपत्ति है कि समझौते में बांग्लादेश के लिए 131 शर्तें हैं, जबकि अमेरिका पर केवल छह शर्तों की बाध्यता है। इसके अलावा डिजिटल व्यापार, ऊर्जा, कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी हितों को प्राथमिकता मिलने की आशंका जताई गई है। समझौते के प्रावधानों को लेकर यह सवाल भी उठा है कि अगर बांग्लादेश किसी तीसरे देश के साथ ऐसा डिजिटल व्यापार समझौता करता है जिसे अमेरिका अपने हितों के खिलाफ मानता है, तो वाशिंगटन समझौता समाप्त करके ऊंचे टैरिफ फिर लागू कर सकता है।

इसके अलावा, अमेरिकी ख्ल्ल की खरीद और अमेरिकी उत्पादों के आयात को लेकर भी विरोध है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों और व्यापारिक नीतियों पर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता खो सकता है। ढाका के शाहबाग और राष्ट्रीय प्रेस क्लब के आसपास हुए विरोध प्रदर्शनों में समझौते को राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की गई। अर्थशास्त्री अनु मोहम्मद ने भी इसे अमेरिकी कॉरपोरेट हितों को फायदा पहुंचाने वाला समझौता बताते हुए संसद में चर्चा के बिना इसे लागू नहीं करने की मांग की है।

साथ ही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी चिंता यह है कि बांग्लादेश एक साथ चीन और अमेरिका पर अपनी आर्थिक निर्भरता बढ़ाता जा रहा है। चीन के साथ ख्ल्ल टर्मिनल और बुनियादी ढांचे से जुड़े समझौते हो रहे हैं, तो अमेरिका के साथ व्यापार, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में नई प्रतिबद्धताएं सामने आ रही हैं। यानी एक तरफ चीन का दखल बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी शर्तों के जरिए बांग्लादेश पर दबाव बना रहा है। देश में विरोध के स्वर इसलिए तेज हो रहे हैं कि कहीं बांग्लादेश अपने राष्ट्रीय हितों को पीछे छोड़कर चीन और अमेरिका की जरूरतों और शर्तों के हिसाब से फैसले लेने वाला देश न बन जाए।

इसके अलावा, बांग्लादेश के सामने आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन्हें समझने के लिए नेपाल का उदाहरण काफी महत्वपूर्ण है। चीन के सहयोग से नेपाल में पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। इस परियोजना पर करीब 21.6 करोड़ डॉलर खर्च हुए। इसमें चीन के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक से कर्ज लिया गया। परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता के लिए बड़े-बड़े अनुमान पेश किए गए और उम्मीद जताई गई कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों तथा पर्यटकों की आवाजाही से एयरपोर्ट अपनी लागत निकाल लेगा।

लेकिन जनवरी 2023 में उद्घाटन के बाद पोखरा एयरपोर्ट नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को आकर्षित करने में नाकाम रहा। यहां अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की स्थिति बेहद कमजोर रही और एक समय केवल सप्ताह में एक नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालित हो रही थी। एयरपोर्ट की आमदनी कर्ज की किस्तों के मुकाबले बेहद कम पड़ रही है। हालात ऐसे बने कि नेपाल को चीन से कर्ज को अनुदान में बदलने का अनुरोध करना पड़ा। निर्माण में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर भी नेपाल की जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की। देखा जाये तो यहां सवाल सिर्फ एयरपोर्ट बनाने का नहीं, बल्कि उस आर्थिक मॉडल का है जिसमें अरबों रुपये की परियोजना खड़ी कर दी जाती है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त यात्री, उड़ानें और राजस्व सुनिश्चित नहीं होते। अंत में परियोजना की चमक दिखाई देती है, लेकिन उसकी वित्तीय जिम्मेदारी देश की जनता और सरकार पर आ जाती है।

साथ ही मालदीव का उदाहरण भी इसी बहस को आगे बढ़ाता है। चीन के सहयोग से वहां बड़े पुल, हवाई अड्डे का विस्तार, आवासीय परियोजनाएं और दूसरे बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट तैयार किए गए। राजधानी के पास एक द्वीप को चीनी कंपनी को 50 साल की लीज पर देने का मामला भी विवादों में रहा। चीनी कर्ज और परियोजनाओं की लागत को लेकर मालदीव में राजनीतिक बहस हुई। देश के बाहरी कर्ज में चीन की बड़ी हिस्सेदारी को लेकर चिंता जताई गई और बाद की सरकारों को कर्ज पुनर्गठन तथा भुगतान की समयसीमा पर बातचीत करनी पड़ी।

इसके अलावा, श्रीलंका का हंबनटोटा बंदरगाह इस बहस का सबसे चर्चित उदाहरण है। चीन की वित्तीय सहायता से बने इस बंदरगाह को अपेक्षित व्यावसायिक सफलता नहीं मिली। बाद में 2017 में श्रीलंका ने चीन की कंपनी को 99 साल की लीज पर इसका संचालन सौंप दिया और इसके बदले लगभग 1.12 अरब डॉलर प्राप्त किए। इस तरह एक रणनीतिक बंदरगाह पर विदेशी कंपनी को इतने लंबे समय तक संचालन अधिकार मिलना अपने आप में गंभीर भू-राजनीतिक घटनाक्रम था।

अब बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह भी चीन और अमेरिका के आर्थिक जाल में उलझता जा रहा है? बांग्लादेश के सामने नेपाल, मालदीव और श्रीलंका के उदाहरण हैं। इन देशों में चीन की मदद से बड़ी-बड़ी परियोजनाएं बनाई गईं। एयरपोर्ट, बंदरगाह और दूसरे बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश हुआ, लेकिन परियोजनाएं उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर सकीं। नतीजा यह हुआ कि इन देशों पर कर्ज का बोझ बढ़ा और कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संचालन में चीन की भूमिका भी बढ़ गई। इसलिए बांग्लादेश में भी यही आशंका जताई जा रही है कि कहीं बड़े निवेश और विदेशी समझौतों के नाम पर देश को ऐसे आर्थिक संकट में तो नहीं धकेला जा रहा, जिससे बाहर निकलना आने वाले वर्षों में मुश्किल हो जाए। बहरहाल, बांग्लादेश के भीतर यह सवाल लगातार गंभीर होता जा रहा है कि तारिक रहमान सरकार देश के हितों को प्राथमिकता दे रही है या चीन और अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियों के सामने सरेंडर करती जा रही है।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय



24- दिङ्नाग सम्प्रदाय का न्यायवाद

गतांक से आगे...

इस संघर्ष की रूपरेखा का विशेत्र निरूपण इस निबन्ध के अगले भाग में दिये गये न्यायशास्त्र के इतिहास में दिया जायगा।

दिङ्नाग सम्प्रदाय का साहित्य इसके विषय में संक्षेप से इतना कहना पर्याप्त होगा कि दिङ्नाग का मुख्य ग्रन्थ जिसने भारतीय दर्शन में क्रान्ति उत्पन्न कर दी प्रमाणसमुच्चय है। भारतीय दर्शन में प्रमाण समुच्चय का वही स्थान है जो कि पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन के इतिहास में बेकन के "Novum Organum" का है।

प्रमाणसमुच्चय के अतिरिक्त दिङ्नाग के अनेक ग्रन्थ हैं, जिनमें से अधिकांश चीनी और तिब्बती भाषा के अनुवादों में विद्यमान हैं और कई मूल संस्कृत रूप में भी प्राप्त हो चुके हैं। दिङ्नाग का न्याय-प्रवेश संस्कृत रूप में श्रीयुत ध्रुव द्वारा सम्पादित और टिप्पणीयुक्त प्रकाशित हो चुका है। वह न्याय का ग्रन्थ है। दिङ्नाग का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ जिसमें वाह्य पदार्थों का खण्डन किया गया है आलम्बनपरीक्षा है। यह भी प्रकाशित हो चुका है।

दिङ्नाग का उत्तराधिकारी दिङ्नाग के समान ही महान् प्रतिभाशाली धर्मकीर्ति था। दिङ्नाग नवीन न्यायवादी बौद्धों के सम्प्रदाय का प्रवर्तृतक है, परन्तु उसे दृढ़ आधार पर स्थापित करने का गौरव धर्मकीर्ति को ही प्राप्त है। यद्यपि कभी-कभी धर्मकीर्ति को दिङ्नाग का शिष्य कहा जाता है, परन्तु यह भ्रमपूर्ण है। वस्तुत: धर्मकीर्ति दिङ्नाग से बहुत पीछे सातवीं सदी में हुए।

यह कहा जाता है कि धर्मकीर्ति दिङ्नाग के एक शिष्य ईश्वरसेन के शिष्य थे। परन्तु धर्मकीर्ति का समय सातवीं सदी का मध्य है, इसलिये दिङ्नाग और धर्मकीर्ति के बीच में अधिक अन्तर होना चाहिये। धर्मकीर्ति का प्रमुख ग्रन्थ प्रमाणवार्त्तिक है।

क्रमश: ...

स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय

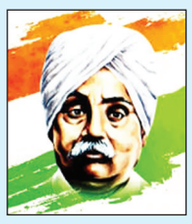

17 नवंबर को भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के धूदिकी गांव में हुआ था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कानून की उपाधि प्राप्त करने के लिए 1880 में लाहौर के राजकीय कॉलेज में प्रवेश ले लिया।

इस दौरान वे आर्य समाज के आंदोलन में शामिल हो गए। लाला जी ने कानूनी शिक्षा पूरी करने के बाद जगरांव में वकालत शुरू कर दी। इसके बाद वे रोहतक और फिर हिसार में वकालत करने लगे। वे आर्य समाज के सक्रिय कार्यकर्ता थे, इस दौरान उन्होंने दयानंद कॉलेज के लिए कोष इकट्ठा करने का काम भी किया। वे हिसार नगर निगम के सदस्य चुने गए और बाद में सचिव भी चुन लिए गए।

स्वामी दयानंद सरस्वती के निधन के बाद लाला जी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एंग्लो वैदिक कॉलेज के विकास के प्रयास करने शुरू कर दिए। उन्होंने हिसार में कांग्रेस की बैठकों में भी भाग लेना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। 1892 में वे लाहौर चले गए। 1897 और 1899 में जब देश के कई हिस्सों में अकाल पड़ा तो लाला जी राहत कार्यों में सबसे अग्रिम मोर्चे पर दिखाई दिए।

जब अकाल पीड़ित लोग अपने घरों को छोड़कर लाहौर पहुंचे तो उनमें से बहुत से लोगों को लालाजी ने अपने घर में ठहराया। उन्होंने बच्चों के कल्याण के लिए भी कई काम किए। जब कांगड़ा में भूकंप ने जबरदस्त तबाही मचाई तो उस समय भी लाला जी राहत और बचाव कार्यों में सबसे आगे रहे। लाला लाजपत राय आजादी के मतवाले ही नहीं, बल्कि एक महान समाज सुधारक और महान समाजसेवी भी थे। यही कारण था कि उनके लिए जितना सम्मान गांधीवादियों के दिल में था, उतना ही सम्मान उनके लिए भगतसिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के दिल में भी था। आजादी की लड़ाई का इतिहास क्रांतिकारियों के विविध साहसिक कारनामों से भरा पड़ा है और ऐसे ही एक वीर सेनानी थे लाला लाजपत राय जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अंग्रेजों ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया तो लाला जी ने सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और विपिनचन्द्र पाल जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिला लिया और अंग्रेजों के इस फैसले की जमकर मुखालफत की। उन्होंने देशभर में स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए अभियान चलाया। 3 मई 1907 को ब्रितानिया हुकूमत ने उन्हें रावलपिंडी में गिरफ्तार कर लिया। रिहा होने के बाद भी लालाजी आजादी के लिए लगातार संघर्ष करते रहे।

लाला जी ने अमेरिका पहुंचकर वहां के न्यूयॉर्क शहर में अक्टूबर 1917 में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नाम से एक संगठन की स्थापना की। लाला जी परदेश में रहकर भी अपने देश और देशवासियों के उत्थान के लिए काम करते रहे। 20 फरवरी 1920 को जब वे भारत लौटे तो उस समय तक वे देशवासियों के लिए एक नायक बन चुके थे। लाला जी ने 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष सत्र में भाग लिया। वे गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े।

नफरती शासकों के लिये सन्देश हैं अमेरिकी उपचुनाव

तनवीर जाफ़री



अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए अमेरिकी संसद (कांग्रेस) के दोनों सदनों यानी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेज़ेनटेटिव्स पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है।रिपब्लिकन पार्टी के दोनों सदनों में बहुमत खोने के बाद अब ट्रंप के शेष कार्यकाल के लिए अमेरिका में विभाजित सरकार की स्थिति बन गई है। 13 नवंबर 2026 तक घोषित आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ऊपरी सदन यानी 100 सीटों वाली यूएस सीनेट ने 55 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी में दो निर्दलीय सांसद भी शामिल हैं जो डेमोक्रेट्स के साथ गठबंधन में हैं। जबकि सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई है। इसी तरह कुल 435 सीटों वाले निचले सदन यानी यूएस हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेनटेटिव्स में जहां बहुमत के लिए 218 सीटों की आवश्यकता होती है। अब तक घोषित 424 सीटों में से डेमोक्रेटिक पार्टी ने 255 सीटें जीत ली हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी को 169 सीटें मिली हैं। यह पिछले 112 वर्षों में हाउस चुनावों में डेमोक्रेट्स की दूसरी सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है। कई रिपब्लिकन गढ़ों में सेंध लगाते हुये डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों ने उन राज्यों में भी कई सीनेट सीटें जीतीं जिन्हें पारंपरिक रूप से रिपब्लिकन गढ़ माना जाता है। इनमें आयोवा,नॉर्थ कैरोलिना, मेन (ट्रॉय डेल जैक्सन), साउथ कैरोलिना (एनी एंड्रयूज़) और मिसिसिपी (स्कॉट कोलोम) जैसी सीटें शामिल हैं। इसी तरह जॉर्जिया में डेमोक्रेट कीशा लांस बॉटम्स अमेरिका के किसी भी राज्य की गवर्नर चुनी जाने वाली पहली अश्वेत महिला बनीं। वहीं न्यू मैक्सिको में डेब हैलैंड अमेरिका की पहली मूल अमेरिकी महिला गवर्नर चुनी गईं। मिशिगन से अब्दुल अल-सैयद देश के पहले मुस्लिम सीनेटर और न्यू हैम्पशायर से क्रिस पप्पास पहले खुले तौर पर समलैंगिक पुरुष सीनेटर चुने गए हैं। माना जा रहा है कि जनवरी 2027 में नई कांग्रेस के शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना अब बेहद कठिन हो जाएगा। सीनेट और हाउस दोनों पर नियंत्रण होने के कारण डेमोक्रेटिक पार्टी अब राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा की जाने वाली न्यायिक और कैबिनेट नियुक्तियों को रोकने की शक्ति रखेगी। इसके साथ ही, डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाली संसदीय समितियां व्हाइट हाउस के कामकाज और नीतियों की जांच भी शुरू कर सकेंगी।

अब सवाल यह है कि क्या शांतिप्रिय अमेरिकी जनता को ट्रंप की मागा Make America Great Again मुहीम रास नहीं आयी या फिर वे ख्ल्ल की आड़ में छुपे ट्रंप के नफ़रती व पूंजीवादी एजेंडे को पहचान गये ? दरअसल ईरान पर अमेरिका द्वारा अकारण युद्ध थोपे जाने और ग़ज़ा नरसंहार के नायक बेंजमिन नेतन्याहू के लगभग हर मानवता विरोधी मिशन में उसका साथ देते रहने वाले ट्रंप ने अपने भाषणों में साम्प्रदायिकता का ज़हर उगलकर पिछले दिनों हुये अमेरिकी उपचुनावों को भी नफ़रती रंग देने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने चुनाव अभियानों के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ कई तीखे और विवादास्पद बयान दिए। इनमें आतंकवाद से जोड़ना, नागरिकता पर सवाल उठाना, नाम बिगाड़ना और धार्मिक क़ानून का डर दिखाना आदि शामिल था। मिसाल के तौर पर मिशिगन से यूएस सीनेट का चुनाव जीतने वाले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल-सैयद चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप के निशाने पर रहे। ट्रंप ने मिशिगन की चुनावी रैलियों में अल-सैयद को बार-बार क्रूर, हिंसक व जिहादी कहा। ट्रंप ने कहा कि वे मिशिगन इसलिए आए हैं ताकि एक जिहादी मुस्लिम ब्रदरहुड सदस्य को अमेरिकी सीनेटर बनने से रोका जा सके। चुनाव से ठीक पहले 1 नवंबर 2026 को एक रैली में ट्रंप ने कहा था कि यदि अल-सैयद चुनाव जीत जाते हैं, तो सीनेट में प्रवेश करने से पहले उनकी जांच करने के लिए वहां मेटल डिटेक्टर लगाने पड़ेंगे। उन्होंने अपने भाषणों में जानबूझकर अब्दुल अल-सैयद को मोहम्मद कहकर संबोधित किया। ट्रंप के नफ़रती बयान की हद तो यह है कि ट्रंप ने मतदाताओं से अपील की कि वे अल-सैयद को हराकर उन्हें वापस वहीं भेज दें जहां से वे आए हैं। जबकि अल-सैयद का जन्म अमेरिका के मिशिगन में ही हुआ है। इसके अतिरिक्त ट्रंप ने अल-सैयद का विरोध करने के लिए 9/11 आतंकी हमलों की तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया।

इतना ही नहीं बल्कि ट्रंप ने हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेनटेटिव्स अर्थात प्रतिनिधि सभा की वर्तमान मुस्लिम सदस्यों इल्हान उमर और रशीदा तालिब पर भी तीखे व्यक्तिगत और राजनीतिक हमले किए। उन्होंने उमर के मूल देश सोमालिया का उपहास उड़ाते हुए कहा कि वह एक ऐसे देश से आती हैं जो असल में एक देश भी नहीं है। अगस्त 2026 में ट्रंप ने सोमाली मूल के लोगों और नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा था कि वे बुद्धिमान नहीं हैं, उनमें कोई योग्यता नहीं है और वे हमें बता रहे हैं कि हमें अपना देश कैसे चलाना है। इसी दौरान उन्होंने ओवल ऑफ़िस में कहा कि हमारे यहां हर जगह जिहादी चुने जा रहे हैं। इसी तरह ट्रंप ने मिशिगन से सांसद रशीदा तालिब और इल्हान उमर के लिए बार-बार कहा कि उन्हें अपने मूल देशों (फ़िलिस्तीन और सोमालिया) वापस चले जाना चाहिए, जबकि रशीदा तालिब का भी जन्म अमेरिका में ही हुआ है। ट्रंप द्वारा केवल कुछ मुस्लिम उम्मीदवारों पर व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, बल्कि पूरे डेमोक्रेटिक ख़ेमे के मुस्लिम नेताओं को लेकर ट्रंप और उनके सहयोगियों ने एक व्यापक नैरेटिव तैयार किया था। ट्रंप और रिपब्लिकन नेताओं ने चुनाव प्रचार में यह दावा किया था कि मुस्लिम उम्मीदवारों के जीतने से अमेरिका में शरिया क़ानून लागू हो जाएगा। नफ़रती ट्रंप ने बिना किसी सबूत के मुस्लिम उम्मीदवारों पर कई प्रतिबंधित संगठनों और मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े होने तक के झूठे व बेबुनियाद आरोप लगाए और अमेरिका के प्रति उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए। ग़ौरतलब है कि 2025 के न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने ज़ोहरान ममदानी के ख़िलाफ़ भी कई तीखे, व्यक्तिगत,नस्लवादी व अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।उन्होंने ममदानी को 100त्न पागल कम्युनिस्ट ,आपदा, अनाकर्षक,विदेशी,देश विरोधी, न्यूयार्क को बर्बाद करने वाला बताते हुए उनपर इस्लामोफ़ोबिक हमले किए थे। परन्तु ममदानी को भी न्यूयार्क के लोगों ने मेयर चुनाव में विजयी बनाया।

रिपब्लिकन पार्टी विशेषकर ट्रंप द्वारा अमेरिकी चुनाव के इतिहास में किये गये इस तरह के सांप्रदायिकतावादी दुष्प्रचार का अमेरिका में पुरज़ोर विरोध किया गया। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और बिल क्लिंटन जैसे कई बड़े नेताओं ने ट्रंप द्वारा मुसलमानों के विरुद्ध किये जाने वाले दुष्प्रचार की आलोचना की। अनेक संगठनों ने भी ट्रंप की इस नफ़रती बयानबाज़ी की निंदा करते हुए इसे नस्लवादी क़रार दिया। उधर इस आक्रामक और इस्लामोफ़ोबिक प्रचार का उल्टा असर यह हुआ कि इसने मुस्लिम और अल्पसंख्यक मतदाताओं को तो लामबंद किया ही साथ ही उदारवादी अमेरिकन ईसाईयों ने भी डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन किया जिसके परिणामस्वरूप 2026 के चुनावों में रिकॉर्ड 7 मुस्लिम उम्मीदवार अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुने गए। नि:संदेह अमेरिका के चुनाव दुनिया के नफ़रती शासकों के लिये साफ़ सन्देश हैं कि नफ़रत की सियासत अधिक समय तक परवान नहीं चढ़ती।

आज का इतिहास

1278 इंग्लैड़ में 680 यहूदियों को नकली मुद्रा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और इनमें से 293 को फाँसी पर लटका दिया गया।
1525 मुग़ल शासक बाबर ने भारत को जीतने के मकसद से सिंध के रास्ते पांचवीं बार प्रवेश किया।
1831 इक्वाडोर और वेनेजुएला ग्रेटर कोलंबिया से अलग हुए।
1869 इंग्लैंड के जेम्स मूरी ने 13 हजार किलोमीटर लंबी पहली साइकिल रेस जीती।
1932 तीसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई।
1933 अमेरिका ने सोवियत संघ को मान्यता देते हुए व्यापार के लिए सहमति दी।
1966 भारत की रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। मिस वर्ल्ड बनने वाली वह पहली एशियाई महिला थी।
1970 सोवियत अंतरिक्ष यान %लुनाखोद-1% चन्द्रतल पर उतरा। रानी लक्ष्मीबाई का एक महत्त्वपूर्ण पत्र जो की उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौज़ी को लिखा था लन्दन में ब्रिटिश लाइब्रेरी के आर्काइव्स में मिला हैं।
1993 अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (नाफ्टा) को मंजूरी दी।
1995 ओसाका में एशिया प्रशांत आर्थिक संघ (एपेक) का सातवां शिखर सम्मेलन शुरू।
1999 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को यूनेस्को ने स्वीकृति दी।
2004 रामेश्वर ठाकुर उड़ीसा के राज्यपाल बने।
2005 श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव सम्पन्न। इटली की संसद ने व्यापक संविधान संशोधनों को मंजूरी प्रदान की। वोल्कर समिति के दस्तावेज उपलब्ध कराने का संयुक्त राष्ट्र पर दबाव बढ़ा।
2006 अमेरिकी सीनेट ने भारत-अमेरिका परमाणु संधि को मंजूरी दी।
2007 जाफना प्रायद्वीप में श्रीलंकाई सेना से मुठभेड़ में 11 लिबरेशन टाइगर मारे गये। आस्कर विजेता पीटर जीनर का निधन।
2008 जे. एस. डब्ल्यू स्टील लिमिटेड ने बेल्कारी में 220 करोड़ की लागत से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के ब्रिटेन की सीबरफील्ड रीवे स्ट्रेक्र के साथ में समझौता किया।
2008 –भारत ने दूसरे वन डे में इंग्लैण्ड को 54 रनों से हराया।
2009 – टी. एस. ठाकुर को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
2012 – मिस्र के मेनफॉल्ट क्षेत्र के समीप एक रेल दुर्घटना में कम से कम 50 स्कूली छात्र मारे गये।
2013 – र

प्रधानमंत्री मोदी से आखिर क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी?

सौरभ वार्ष्णेय

भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच राजनीतिक टकराव कोई नई बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से दोनों नेताओं के बीच विचारों, नीतियों और राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर संघर्ष जारी है। लेकिन जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को आमने-सामने सार्वजनिक बहस की चुनौती देते हैं, तो यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर राहुल गांधी मोदी से क्या कहना चाहते हैं? क्या वे प्रधानमंत्री से देश के ज्वलंत मुद्दों पर सीधे जवाब मांग रहे हैं, या फिर इस चुनौती के माध्यम से अपनी राजनीतिक भूमिका और विपक्ष की प्रासंगिकता को नए सिरे से स्थापित करना चाहते हैं? दरअसल, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच संवाद की अपनी एक महत्वपूर्ण परंपरा रही है। संसद वह सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है, जहां सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, नीतियों की समीक्षा होती है और देश के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। लेकिन जब संसद के भीतर बहस को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए विपक्ष का प्रमुख नेता प्रधानमंत्री को सार्वजनिक मंच पर आमने-सामने बहस की चुनौती देता है, तो यह केवल दो नेताओं के बीच व्यक्तिगत मुकाबला नहीं रह जाता, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद की गुणवत्ता से जुड़ा प्रश्न बन जाता है।

राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को रोजगार, महंगाई, किसानों की समस्याओं, सामाजिक न्याय, चीन के साथ सीमा विवाद, चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर घेरते रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने से बचती है और विपक्ष की आवाज को पर्याप्त स्थान नहीं मिलता। विशेष रूप से चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। हालांकि इन आरोपों को लेकर राजनीतिक मतभेद हैं और उनके समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणों की स्वतंत्र जांच भी महत्वपूर्ण है।

राहुल गांधी की बहस की चुनौती को इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में समझना होगा। वे संभवतः यह संदेश देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े राजनीतिक पद पर हैं, इसलिए उनसे देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे सवाल पूछे जाने चाहिए। उनका तर्क है कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री भी सवालों से ऊपर नहीं हो सकते। जनता ने सरकार को शासन करने का अधिकार दिया है, लेकिन उसी जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए।दूसरी ओर, भाजपा और सत्तापक्ष का दृष्टिकोण इससे अलग है। भाजपा नेताओं का कहना है कि संसद लोकतांत्रिक बहस का उचित मंच है और विपक्ष को वहीं अपनी बात रखनी चाहिए। सत्तापक्ष का यह भी तर्क रहा है कि राजनीतिक आरोप लगाने के बजाय विपक्ष को तथ्यों और प्रमाणों के साथ अपनी बात सामने रखनी चाहिए। इस प्रकार बहस की मांग के साथ ही यह प्रश्न भी खड़ा होता है कि क्या राजनीतिक संवाद संसद तक सीमित रहना चाहिए या देश के सामने खुले मंच पर भी ऐसी बहस होनी चाहिए?

यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के बीच सार्वजनिक बहस



भारतीय संसदीय व्यवस्था की अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। भारत में सरकार की जवाबदेही संसद, संसदीय समितियों, प्रश्नकाल, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र संस्थाओं और जनता के प्रति राजनीतिक उत्तरदायित्व के माध्यम से तय होती है। फिर भी सार्वजनिक बहस लोकतांत्रिक संवाद को मजबूत करने का एक माध्यम बन सकती है।

राहुल गांधी के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। उन्हें केवल सवाल उठाने तक अपनी राजनीति सीमित नहीं रखनी होगी, बल्कि यह भी बताना होगा कि जिन समस्याओं को लेकर वे सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उनका समाधान उनकी पार्टी किस प्रकार करेगी। बेरोजगारी का समाधान क्या होगा? किसानों की आय बढ़ाने की व्यावहारिक योजना क्या होगी? महंगाई पर नियंत्रण के लिए कौन-से ठोस कदम उठाए जाएंगे? सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता को किस प्रकार लागू किया जाएगा? इन सवालों के जवाब भी विपक्ष की राजनीतिक विश्वसनीयता के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने सरकार से पूछे जाने वाले सवाल।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के सामने भी यह चुनौती है कि वे आलोचनाओं को केवल राजनीतिक विरोध मानकर खारिज न करें। लोकतंत्र में असहमति को स्थान देना और गंभीर सवालों का तथ्यात्मक जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि किसी आरोप में तथ्य नहीं हैं तो सरकार को प्रमाणों के साथ उसका खंडन करना चाहिए। लेकिन यदि कोई सवाल जनहित से जुड़ा है तो उसका जवाब देना लोकतांत्रिक जवाबदेही का हिस्सा है।

राजनीति में बहस का उद्देश्य किसी एक नेता को विजेता और दूसरे को पराजित घोषित करना नहीं होना चाहिए। देश को यह जानने का अधिकार है कि सत्ता पक्ष के पास अपनी नीतियों के पक्ष में क्या तर्क हैं और विपक्ष के पास वैकल्पिक नीतियों का कौन-सा खाका है। जनता केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि परिणाम, योजनाएं और भविष्य की दिशा जानना चाहती है।

राहुल गांधी की चुनौती को कांग्रेस की बदलती राजनीतिक रणनीति के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। कांग्रेस लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री को सीधे बहस की चुनौती देना राजनीतिक विमर्श को सरकार की उपलब्धियों और कमियों से हटाकर जवाबदेही के सवाल पर केंद्रित करने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन इस रणनीति की सार्थकता इस बात पर निर्भर करेगी कि कांग्रेस अपने आरोपों को कितनी मजबूती से प्रमाणित करती है और जनता के सामने कितना विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करती है।

वहीं प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी यह अवसर हो सकता है कि वे देश के सामने अपनी सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को विस्तार से रखें। लोकतंत्र में मजबूत नेतृत्व का अर्थ केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि आलोचना सुनने और उसका जवाब देने की क्षमता भी है।

सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से बहस जीतना चाहते हैं या प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी की चुनौती स्वीकार करते हैं अथवा नहीं। असली सवाल यह है कि देश के करोड़ों नागरिक जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन पर राजनीतिक नेतृत्व कितनी गंभीरता से संवाद करता है। भारत का लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति, एक दल या एक विचारधारा से बड़ा है। प्रधानमंत्री की जवाबदेही और विपक्ष की जिम्मेदारी, दोनों लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यदि राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो उन्हें तथ्यों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए और यदि प्रधानमंत्री मोदी के पास उन सवालों के जवाब हैं तो उन्हें जनता के सामने रखने में संकोच नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और जवाब देना सत्ता की जिम्मेदारी। लेकिन जनता की अपेक्षा इससे भी आगे है। उसे केवल मोदी और राहुल के बीच राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि देश के भविष्य पर सार्थक बहस चाहिए। आखिरकार लोकतंत्र में असली विजेता कोई नेता नहीं, बल्कि जनता होनी चाहिए।

कठिन और पवित्र अनुष्ठान है महापर्व छठ

किरण चोपड़ा

हमारे यहां कार्तिक महीना पुण्य कमाने का एक आध्यात्मिक अवसर है। प्राकृतिक रूप से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। सब जानते हैं कि भारत त्यौहारों और परंपराओं का देश है। यहां मनाए जाने वाले प्रत्येक पर्व का अपना धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। इन पवित्र त्योहारों में छठ महापर्व का विशेष स्थान है।

इस कड़ी में छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन, स्वच्छता, प्रकृति प्रेम, सामाजिक एकता और पारिवारिक संस्कारों का अद्भुत संगम है। विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तरप्रदेश अर्थात पूर्वांचलियों का यह पर्व आज देश के लगभग हर हिस्से में अपनी पहचान बना चुका है।

भले ही समाज तेजी से आधुनिकता, भौतिकवाद और व्यक्तिगत स्वार्थ की ओर बढ़ रहा है, फिर भी छठ महापर्व हमें अपनी संस्कृति, प्रकृति और सामाजिक जिम्मेदारियों से जोड़ने का महत्वपूर्ण संदेश देता है। छठ पूजा भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना का पर्व है। सूर्य को जीवन, ऊर्जा, प्रकाश और स्वास्थ्य का आधार माना गया है। छठ पूजा चार दिनों तक चलने वाला कठिन और पवित्र अनुष्ठान है। इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है। खरना के बाद अस्ताचल और उदयगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तब व्रत का समापन किया जाता है। पवित्र व्रत की यह परंपरा समाज को एक गहरा संदेश देती है कि हमें केवल सफलता और उपलब्धियों का सम्मान नहीं करना चाहिए, बल्कि कठिन समय और संघर्ष के दौर में भी सम्मान और विश्वास बनाए रखना चाहिए।



आज के समय में प्रकृति प्रेम बहुत आवश्यक है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रकृति के प्रति सम्मान है। इस पर्व में सूर्य, जल, वायु और पृथ्वी के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। पूजा के लिए नदी, तालाब और जलाशयों के किनारे जाना हमारी जल-संपदा के महत्व को भी दर्शाता है। देखा जाए तो आज देश के सामने प्रदूषण, जल संकट, नदियों की गंदगी और पर्यावरण असंतुलन जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। ऐसे समय में छठ पूजा हमें याद दिलाती है कि जल केवल पूजा का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन का आधार है लेकिन केवल पूजा करने से पर्यावरण की रक्षा नहीं होगी। हमें अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना होगा। छठ घाटों पर प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, पूजा सामग्री को जल में फेंकने के बजाय उचित स्थान पर रखना चाहिए और नदियों तथा तालाबों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यदि छठ पूजा के अवसर पर प्रत्येक नागरिक स्वच्छता का संकल्प ले तो यह पर्व पर्यावरण संरक्षण के एक बड़े सामाजिक अभियान का रूप ले सकता है। यदि हम इस पर्व के मूल संदेश को अपने दैनिक जीवन में उतार सकें तभी छठ पूजा की सार्थकता है।

खुशियों की ईद: खरगे के बयान से कितना लाभ, कितना नुकसान?

सत्येंद्र प्रताप सिंह

दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि यह देशभर में मनाया जाने वाला बड़ा त्योहार है और इसे %खुशियों की ईद% कहा जा सकता है। उन्होंने त्योहार के बहाने देश में शांति बनाए रखने, आपसी मतभेद भुलाने और राष्ट्रीय एकता मजबूत करने की अपील भी की।

खरगे के बयान का मूल भाव खुशियों और उत्सव की साझी संस्कृति बताना था। लेकिन क्या राजनीतिक मंच से दिए गए ऐसे संदेश के लिए शब्दों का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है? क्या वह अपनी बात बिना किसी दूसरे धर्म के त्योहार का संदर्भ दिए भी कह सकते थे?

भाजपा ने खरगे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया कि दीपावली की अपनी धार्मिक पहचान, परंपरा और सांस्कृतिक महत्व है। उसे ईद से जोड़ने की क्या जरूरत थी?

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पूछा कि क्या खरगे और राहुल गांधी ईद को %खुशियों की दिवाली% कहने का साहस दिखाएंगे? भाजपा ने इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति और हिंदू भावनाओं की अनदेखी से जोड़ने की कोशिश की। यहां भाजपा की आपत्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। उसने कांग्रेस के पुराने धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर दिए गए बयानों को भी इस विवाद से जोड़ दिया।

कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को राजनीतिक विवाद पैदा करने की कोशिश बताया। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि ईद का अर्थ त्योहार है और खरगे ने इसी व्यापक अर्थ में इस



शब्द का इस्तेमाल किया है।

उनका तर्क था कि बयान को उसके पूरे संदर्भ में समझना चाहिए। खरगे ने किसी धर्म या त्योहार का अपमान नहीं किया, बल्कि खुशियों और आपसी सद्भाव की बात कही लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की यह सफाई आम लोगों तक उसी तरह पहुंचेगी, जिस तरह भाजपा का आरोप पहुंच रहा है?

इस विवाद का एक दिलचस्प पहलू मुस्लिम नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने खरगे पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उनके हाथ में होता तो वोट बैंक की राजनीति के लिए वे दीपावली के दिन ही लोगों को %ईद मुबारक% कह देते। उन्होंने कांग्रेस पर धार्मिक त्योहारों को लेकर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया।

इसके विपरीत कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने खरगे के बयान का बचाव किया। उनका कहना था कि खुशी व्यक्त करने के लिए ईद का इस्तेमाल एक रूपक के तौर पर भी होता है। आम बोलचाल में किसी के लंबे समय बाद दिखाई देने पर %ईद का चांद हो गए% कहा जाता है। उनके मुताबिक ईद खुशी का पर्याय है।

लेकिन एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान की प्रतिक्रिया कांग्रेस के लिए असहज करने वाली रही। उन्होंने भी खरगे के बयान को राजनीतिक दिखावा और किसी खास वोट बैंक को खुश करने की कोशिश बताया। उनका कहना था कि दीपावली और ईद दोनों की अपनी अलग पहचान है और दोनों त्योहारों का सम्मान होना चाहिए।

यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जब मुस्लिम समुदाय के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी एक जैसी नहीं हैं, तब क्या इस पूरे विवाद को केवल हिंदू बनाम मुस्लिम के नजरिये से देखना उचित होगा?

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म सद्भाव के संदेश को किस तरह प्रस्तुत करती है। खरगे के बयान को पार्टी एक ऐसे प्रयास के रूप में पेश कर सकती है, जिसमें अलग-अलग धर्मों के त्योहारों को साझा खुशियों से जोड़ने की कोशिश की गई।

लेकिन भाजपा इसे कांग्रेस की कथित तुष्टीकरण की राजनीति के उदाहरण के रूप में प्रचारित कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह विवाद केवल एक बयान का बचाव करने तक सीमित नहीं रहेगा। उसे यह भी बताना होगा कि उसकी धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का समान सम्मान कैसे करती है।

दूसरी तरफ भाजपा को भी यह स्पष्ट करना होगा कि क्या किसी दूसरे धर्म के त्योहार का सकारात्मक संदर्भ देना अपने आप में उस त्योहार की पहचान या परंपरा का अपमान है?

भारत में दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व और दूसरे त्योहार सामाजिक मेलजोल के अवसर भी बनते रहे हैं। एक-दूसरे के त्योहारों की शुभकामनाएं देना भारतीय समाज की साझी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ऐसे अवसर भी राजनीतिक संदेश देने का माध्यम बनते जा रहे हैं।

खरगे का बयान सद्भाव की भावना से दिया गया था या उसमें राजनीतिक संदेश भी निहित था, यह बहस का विषय हो सकता है। उसी तरह भाजपा की आपत्ति सांस्कृतिक पहचान के सम्मान से जुड़ी है या राजनीतिक विरोध का हिस्सा है, इस पर भी सवाल उठेंगे।

असली सवाल यह है कि क्या त्योहारों की खुशियों को साझा करने के लिए एक-दूसरे के त्योहारों का उदाहरण देना जरूरी है? और क्या राजनीतिक दल हर ऐसे संदेश को वोट बैंक के चश्मे से देखेंगे?

खुशियों की ईद कहने से शुरू हुआ यह विवाद आखिरकार कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष राजनीति, भाजपा की सांस्कृतिक राजनीति और विपक्षी खेमे के भीतर अलग-अलग विचारों की परीक्षा बन गया है। इसका राजनीतिक लाभ या नुकसान केवल बयान से नहीं, बल्कि जनता इसे किस संदर्भ में ग्रहण करती है, उससे तय होगा।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत आ रहा पाकिस्तान

अभिनय आकाश

इसी महीने भारत में होने वाले एसईओ समिट में पाकिस्तान ने आने की हामी भर दी है। मुसद्दीक मसूद मलिक भारत में एसईओ समिट में शामिल होने के लिए आएंगे। 2023 में जब भारत में हुई एसईओ समिट में शामिल होने के लिए बिलावल भुट्टो आए थे। इसी बीच में एस जयशंकर भी एसईओ का समिट जब पाकिस्तान में हुआ तो वहां गए थे। लेकिन अहम बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहलगाम में पाकिस्तान ने हमला किया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से किया गया मई 7 मई 2025 तब से लेकर उसके बाद से अगर बात करें तो यह पाकिस्तान की पहली यात्रा होगी। पाकिस्तान के किसी मंत्री की पहली यात्रा होगी। एसईओ का समिट था तो जाहिर सी बात है भारत को न्योता भेजना था। भारत ने न्योता भेजा भी। लंबे वक्त तक अटकलें चलती रही। पाकिस्तान ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब आखिरकार पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। एसईओ सिविलाइजेशन डायलॉग जो नई दिल्ली में होने वाला है उसमें पाकिस्तान के मंत्री शामिल होंगे। इससे पहले गोवा में बिलावल भुट्टो शामिल हुए थे। दिल्ली में 20 से 22 नवंबर तक लाल किले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए मंत्री मुसद्दीक मसूद भारत आएंगे। भारत की ओर से पाकिस्तान को इस कार्यक्रम का न्योता भेजा गया था जिसके बाद इस्लामाबाद से सकारात्मक जवाब आया। पाकिस्तानी मंत्री का दिल्ली में आयोजित होने वाले एसईओ के कार्यक्रम में आना इसलिए अहम है क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते पिछले कुछ महीनों से बेहद बेहद ही निचले स्तर पर कह सकते हैं।

एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) का प्रतिनिधित्व चीन, भारत, रूस, ईरान, पाकिस्तान, बेलारूस और मध्य एशियाई



देशों जैसे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान द्वारा किया जाता है। स्ष्ठह के लगभग सभी सदस्य देश प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनका इतिहास ईसा पूर्व (BCE) युग तक जाता है। सभ्यतागत संबंध सक्रिय राजनयिक विषय हैं, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से स्पष्ट होता है जो उत्तर और पश्चिम भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी फैले हुए हैं, जहां सिंध और अन्य स्थानों पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थित हैं। इस मंच से कुछ राजनयिक अवसर प्रदान करने की उम्मीद है, साथ ही यह इतिहासकारों और नागरिक समाज के लोगों के बीच संवाद का अवसर भी देगा।

संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार, पुराना किला का यह स्थल भारत के सभ्यतागत, राजनीतिक और पुरातात्विक इतिहास का एक उत्कृष्ट नमूना है, क्योंकि इस स्थान में लगभग 3000 वर्षों का सांस्कृतिक क्रम मौजूद है, जिसमें पूर्व-मौर्य, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, गुप्तोत्तर, राजपूत, सल्तनत और मुगल काल शामिल हैं। इस किले का निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं (वंश के दूसरे सम्राट) ने करवाया था और बाद में मुगलों के पास वापस आने से पहले इस पर शेर शाह सूरी का नियंत्रण था। यह किला पहले भी एक राजनयिक स्थल के रूप में काम कर चुका है; उदाहरण के लिए, 2006 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की यात्रा के दौरान, जिनकी मेजबानी भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर मुहर लगने के समय यहीं की गई थी। इस फोरम (मंच) में कौन-कौन भाग लेगा?

इसमें 10 SCO सदस्य देशों, दो पर्यवेक्षक देशों और स्ष्ठह के 15 संवाद भागीदारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस समूह में सदस्य देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, इतिहासकार, संग्रहालय पेशेवर, प्रतिष्ठित शिक्षाविद और पत्रकार शामिल होंगे। SCO सिविलाइजेशनल फोरम की रूपरेखा क्या होगी?इस फोरम में चार विषयगत (थीमेटिक) सत्र शामिल होंगेन्मठवासी मार्ग (मोनास्टिक ट्रेल्स): धर्म और दार्शनिक परंपराएं;कला और वास्तुकला: सभ्यताओं में साझा सौंदर्यशास्त्र;भाषा, साहित्य, लिपि और पांडुलिपि परंपराएं; औरसांस्कृतिक अभिव्यक्तियां और जीवंत परंपराएं।इन सत्रों में होने वाली चर्चाओं में स्ष्ठह क्षेत्र में ऐतिहासिक संबंधों, साझा ज्ञान प्रणालियों, कलात्मक प्रभावों, साहित्यिक परंपराओं और जीवंत सांस्कृतिक प्रथाओं की पड़ताल की जाएगी। इस फोरम में भाग लेने वाले देशों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शामिल होंगी।

पाकिस्तान ने 1 सितंबर 2026 से 2026-27 के लिए एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की क्रमिक (रोटेटिंग) अध्यक्षता संभाली है। स्ष्ठह में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। मलिक की यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के लिए नहीं है। वे स्ष्ठह के एक सदस्य देश के प्रतिनिधि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम (सभ्यता संवाद कार्यक्रम) का पहला सत्र इस महीने के अंत में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पूरे यूरेशिया में सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भारत ने यह पहल शुरू की है। भारत ने एससीओ के सभी 10 सदस्य देशों को सभ्यता संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस कार्यक्रम में सभी सदस्य देशों की मेजबानी करने के लिए तैयार है।

नई दिल्ली में 20 से 22 नवंबर के दौरान आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन (समिट) में विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच संवाद तथा आपसी संपर्क बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम की घोषणा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने 20 अक्टूबर को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में की थी। उस समय वे एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे थे।

भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को आमंत्रित किया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने जलवायु परिवर्तन और समन्वय मंत्री को नामित किया है। पाकिस्तान सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले का विरोध करता रहा है और इस फैसले को वापस लेने के लिए अभियान चला रहा है। इसके लिए पाकिस्तान सरकार हाल के महीनों में सिंधु नदी को न केवल देश के लिए पानी के स्रोत के रूप में, बल्कि अपनी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में भी पेश कर रही है, क्योंकि देश में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कई अन्य ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। 18 अप्रैल 2026 को विश्व विरासत दिवस (वर्ल्ड हेरिटेज डे) के अवसर पर प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने अपने संबोधन में सिंधु घाटी सभ्यता का ज़िक्र करते हुए कहा पाकिस्तान की सांस्कृतिक विरासत एक बहुआयामी सभ्यता से समृद्ध है।

वोट चोरी के बहाने अराजक आंदोलन

सुरेश हिंदुस्तानी

देश के वर्तमान राजनीतिक वातावरण को लेकर जनमानस में अनेक प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब स्वाभाविक रूप से उन राजनीतिक दलों की ओर से अवश्य ही आना चाहिए, जो राजनीतिक धुरी के रूप में अपने आपको स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में वोट चोरी को मुख्य मुद्दा बनाकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहा है, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी जमकर प्रत्युत्तर देने का साहसिक प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में जनता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र के मायने भी यही हैं कि देश में जनता की सरकार है, राजनीतिक दलों की नहीं। जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में इन्हें चुनकर भेजती है। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और जनादेश की अभिव्यक्ति हैं। वर्तमान में विपक्ष खासकर कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। यह विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सवाल उठाने और संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा कर राजनीतिक अराजकता पैदा करने के बीच एक स्पष्ट अंतर है। दुर्भाग्य से कांग्रेस आज इसी अंतर को समझने में असफल दिखाई दे रही है। वोट चोरी के आरोपों को आधार बनाकर आंदोलन खड़ा करने की उसकी कोशिश राजनीतिक रणनीति से अधिक अपनी हताशा और दिशाहीनता का प्रदर्शन प्रतीत होती है।

लोकतंत्र में विरोध का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण उसकी मर्यादा भी है। यदि किसी राजनीतिक दल को लगता है कि चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता हुई है, तो उसके पास संवैधानिक और कानूनी मंच उपलब्ध हैं। उसे तथ्यों, प्रमाणों और ठोस तर्कों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन किसी संवैधानिक पद पर बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को आंदोलन का केंद्रीय विषय बना देना क्या उचित राजनीतिक तरीका है? मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की एक निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया है। उसे राजनीतिक दबाव और सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा के अनुकूल नहीं कही जा सकती।

कांग्रेस को यह समझना होगा कि चुनाव में लगातार मिल रही पराजय का पूरा दोष चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त पर डालकर वह अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। कांग्रेस की चुनावी चुनौतियां आज की नहीं हैं। पार्टी लंबे समय से अनेक राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर जनसमर्थन खोती रही है। इसके पीछे संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व का संकट, स्थानीय स्तर पर प्रभावी नेतृत्व का अभाव और जनता से टूटता संवाद जैसे अनेक कारण हैं। इन कारणों का आत्मविश्लेषण करने के बजाय हर पराजय के बाद चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाना समस्या का समाधान नहीं है।

कांग्रेस ने अपने आंदोलन के लिए समय का चयन भी ठीक नहीं किया। देश में दीपावली का उत्सव निकट है। बाजारों में रौनक है, व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को सजाने, कारोबार बढ़ाने और ग्राहकों की तैयारी में व्यस्त हैं। आम परिवार खरीदारी, त्योहार की तैयारियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों में जुटे हैं। ऐसे समय में व्यापक जनभागीदारी की अपेक्षा करना व्यावहारिक राजनीतिक समझ का परिचय नहीं देता। स्वाभाविक है कि आंदोलन में अपेक्षित संख्या नहीं जुट पाई। राजनीति केवल नारे लगाने से नहीं चलती, इसके लिए समाज की मन:स्थिति, समय और परिस्थितियों को समझना भी आवश्यक है। विशेष रूप से व्यापारी वर्ग की भावनाओं को नजरअंदाज करना कांग्रेस की रणनीतिक भूल कही जा सकती है। त्योहारों का समय व्यापारियों के लिए वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी अवसरों में से एक होता है। व्यापारी वर्ग यदि आंदोलन के समय और स्वरूप को लेकर अपनी असहमति व्यक्त कर रहा था, तो कांग्रेस नेतृत्व को उसके अनुरोध पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था। लोकतांत्रिक राजनीति का अर्थ समाज के विभिन्न वर्गों की परेशानियों और प्राथमिकताओं को समझना है, न कि अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार उनसे सहभागिता की अपेक्षा करना।



हिन्दू धर्म के हिसाब से वैसे तो हर ग्यारस तिथि को महत्वपूर्ण माना गया है और कई लोग इस तिथि पर उपवास रखते हैं परन्तु देव उठनी ग्यारस का विशेष महत्व है. ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक माह की एकादशी को भगवान विष्णु चार माह बाद योगनिद्रा से जागे थे और इसलिए चातुर्मास के बाद अब यह पहला मुहूर्त होता है जिसे सभी कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है. सबके पालनकर्ता श्री हरि हैं, इसलिए सनातन धर्मावलंबी प्रत्येक मांगलिक कार्यों का शुभारंभ भगवान विष्णु को साक्षी मानकर करते हैं. आज के दिन तुलसी विवाह से शादी का मौसम भी शुरू होता है. तुलसी विवाह एक रस्म है जिसमें आज के दिन तुलसी जी का विवाह विष्णु भगवान के साथ किया जाता है.

देवउठनी एकादशी

विष्णु-लक्ष्मी की उपासना का दिन

दीपावली के 11 दिन बाद देव प्रबोध उत्सव और तुलसी के विवाह को देवउठनी एकादशी कहते हैं। एकादशी का यह पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है। क्षीरसागर में शयन कर रहे श्री हरि विष्णु को जगाकर उनसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत कराने की प्रार्थना की जाती है। श्रद्धालु घरों के द्वार पर गन्ने के मंडप बनाकर श्रद्धालु भगवान लक्ष्मीनारायण का पूजन कर उन्हें बेर, बेर की भाजी, आंवला सहित अन्य मौसमी फल व सब्जियों के साथ पकवान का भोग अर्पित किए जाते हैं। संध्या में शालिग्राम की प्रतिमा व तुलसी का पौधा मंडपम् उनका विवाह कराया जाता है। इसके बाद मण्डप की परिक्रमा करते हुए भगवान से कुँवारों के विवाह कराने और विवाहितों के गृहस्थी बसाने की प्रार्थना की जाती है। देव जागरिकाओं से घरों को रोशन किया जाएगा और कल पटाखे चलाकर खुशियां मनाते हैं।

कैसे करें ग्यारस के दिन पूजन

- देवउठनी ग्यारस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए।
- इस दिन घर के दरवाजे को पानी से स्वच्छ करना चाहिए, फिर चूने व गेरू से देवी बनाने चाहिए।
- उसके ऊपर गन्ने का मंडप सजाने के बाद देवताओं की स्थापना करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करते समय गुड़, रूपये, रोली, अक्षत, चावल, पुष्प रखना चाहिए।
- पूजन में दीप जलाकर देव उठने का उत्सव मनाते हुए 'उठो देव बैठो देव' का गीत गाना चाहिए।

सामग्री गंगा जल, शुद्ध गिट्टी, कुश, सामान्य, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चावल, लाल वस्त्र, कपूर, पान, घी, सुपारी, रोली, दूध, दही, शहद, फल, शक्कर, फूल, नैवेद्य, गन्ने, ढक्कन सामग्री, तुलसी पौधा, विष्णु प्रतिमा।

क्यों मनाते है देवउठनी एकादशी

पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु व जलंधर के बीच युद्ध होता है। जलंधर की पत्नी तुलसी पतिव्रता नारी है। इसके कारण विष्णु जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को पराजित करने के लिए भगवान शिव के तेज जलंधर का रूप धारण कर तुलसी का सतीत्व भंग करने पहुँच गए। तुलसी का सतीत्व भंग होते ही भगवान विष्णु जलंधर को युद्ध में पराजित कर देते हैं। युद्ध में जलंधर मारा जाता है। भगवान विष्णु तुलसी को वरदान देते हैं कि वे उनके साथ पूजी जाएँगी। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा रामा को लक्ष्मण रूप हो जाने व राम को गंगा के जल रूप हो जाने का शाप देती है। रामा व गंगा दोनों ने भगवान कृष्ण को पाषाण रूप हो जाने का शाप दे दिया। इसके कारण ही तुलसी, गंगा नदी व कृष्ण शालिग्राम के रूप में प्रसिद्ध हुए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन शालिग्राम, तुलसी व शंख का पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। देव प्रबोधिनी एकादशी का महत्व शास्त्रों में उल्लेखित है। गोधूलि बेला में तुलसी विवाह करने का पुण्य लिया जाता है। एकादशी व्रत और कथा श्रवण से स्वर्ग की प्राप्ति होती है।

देवोत्थान एकादशी

कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी पूजन का उत्सव मनाया जाता है, किन्तु उत्तर भारत में इसका विशेष महत्व है। तुलसी को विष्णु-प्रिया भी कहते हैं। वैसे तो तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल नवमी की तिथि ठीक है परंतु कुछ लोग एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन कर पाँचवें दिन तुलसी का विवाह करते हैं। तुलसी विवाह की यही पद्धति अधिक प्रचलित है। इस दिन से हिन्दू समाज में विवाहादि मांगलिक कार्य भी पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। इस एकादशी के उपवास से अनंत फल की प्राप्ति होती है।



देवउठनी एकादशी व्रत कथा

कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, देवउठनी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर-चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला- महाराज! कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं। किन्तु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा- महाराज! इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। मैं भूखा ही मर जाऊँगा। मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ, तब राजा ने उसे आटा-दाल-चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुँचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा- आओ भगवान! भोजन तैयार है।

पंद्रह दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं। इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला- मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए।

राजा की बात सुनकर वह बोला- महाराज! यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा- हे भगवान! यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूँगा। लेकिन भगवान नहीं आए, तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा-पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत-उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता, जब तक मन शुद्ध न हो। इसके बाद राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत-उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ।

कैसे करें व्रत-पूजन

- सभी स्त्रियां इस दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन में चौक बनाएं।
- पश्चात भगवान विष्णु के चरणों को अलंकृत रूप से अंकित करें।
- फिर दिन भर तेज धूप में विष्णु के चरणों को ढंक दें।
- देवउठनी एकादशी को रात्रि के समय सुभाषित श्लोक पाठ, भगवत कथा और पुराणादि का श्रवण और भजन आदि का गायन करें।
- घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े और वीणा बजाएं।
- विविध प्रकार के खेल-कूद, लीला और नाच आदि के साथ इस रात्रि का उत्सव करते हुए भगवान को जगाएं -

उत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पतये। त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तं भवेदिदम्॥
उत्थिते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव। गतमेघा विनष्टांश निर्मलं निर्मलंदिशः॥
शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव।

इसके बाद विधिवत पूजा करें।

कैसे करें व्रत-पूजन

- पूजन के लिए भगवान का मन्दिर अथवा सिंहासन को विभिन्न प्रकार के लता पत्र, फल, पुष्प और वंदनवार आदि से सजाएं।
- आंगन में देवोत्थान का चित्र बनाएं, तत्पश्चात फल, पकवान, सिंघाड़े, गन्ने आदि एकत्रकर डलिया से ढंक दें तथा दीपक जलाएं।
- विष्णु पूजा या षोडशोपचार पूजन विधान अथवा रामार्चनचन्द्रिका आदि के अनुसार श्रद्धापूर्वक पूजन तथा धूपक, कपूर आदि से आरती करें।
- इसके बाद इस मंत्र से पुष्पांजलि अर्पित करें -

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।
तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्तिदेवाः॥

पश्चात इस मंत्र से प्रार्थना करें -

इयं तु द्वादशी देव प्रबोधाय विनिर्मिता। तत्रैव सर्वतीर्थानां निवासोऽयमीश्वर॥
इदं व्रतं मया देव कृतं प्रीत्यै तव प्रभो। न्यून सम्पूर्णतां यातु त्वत्प्रसादाज्जनार्दन॥

स्नान के पश्चात भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प करें। संकल्प के बाद षोडशोपचार विधि से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजन के बाद भगवान को दूध से बने नैवेद्य का भोग लगाएं। रात्रि में घी के दीपक से आरती करें। रात्रि में जागरण करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। द्वादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भोजन करें।



देव उठनी ग्यारस का महत्व

हिन्दू धर्म के हिसाब से वैसे तो हर ग्यारस तिथि को महत्वपूर्ण माना गया है और कई लोग इस तिथि पर उपवास रखते हैं परन्तु देव उठनी ग्यारस का विशेष महत्व है. ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक माह की एकादशी को भगवान विष्णु चार माह बाद योगनिद्रा से जागे थे और इसलिए चातुर्मास के बाद अब यह पहला मुहूर्त होता है जिसे सभी कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है. सबके पालनकर्ता श्री हरि हैं, इसलिए सनातन धर्मावलंबी प्रत्येक मांगलिक कार्यों का शुभारंभ भगवान विष्णु को साक्षी मानकर करते हैं. आज के दिन तुलसी विवाह से शादी का मौसम भी शुरू होता है. तुलसी विवाह एक रस्म है जिसमें आज के दिन तुलसी जी का विवाह विष्णु भगवान के साथ किया जाता है. आज के प्रसंग में देखें तो चातुर्मास के बाद देव उठनी ग्यारस से पूरे बाजार में हलचल शुरू हो जाती है. शादी का मुहूर्त निकलने के कारण लोग खरीदी में लग जाते हैं और इस तरह व्यापार-व्यवसाय में बड़ा उछाल आता है. भारत की यह सामाजिक संरचना ही यहां की आर्थिक संरचना को इतना मजबूत बनाती है. तीज-त्यौहार सिर्फ खुशियों का बसना नहीं बल्कि व्यापार-व्यवसाय को बढ़ावा देना का भी कहलाता है. छत्तीसगढ़ के उत्तरी भारत में कभी भी रिसेशन नहीं आ सकता. मैं देव उठनी ग्यारस और सभी त्यौहारों को बहुत शुभ मानता हूँ. देव उठनी ग्यारस का धार्मिक महत्व और हमारी संस्कृति का व्यवहारिक दृष्टिकोण देखकर भारतीय संस्कृति के प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई. आज के दिन बड़े जगहों पर सामूहिक विवाह का आयोजन भी रहता है. यह भी हमारी संस्कृति का एक अमूल्य पहलू है. जो असमर्थ लोग शादी में ज्यादा खर्च नहीं कर सकते उनके लिए समाज द्वारा की गई यह कुशल व्यवस्था अत्यंत सराहनीय है. आज देव उठनी ग्यारस के दिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिनकी आपूर्ति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शय्या पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि से कमल है, जो सब देवताओं द्वारा पूज्य हैं, जो संपूर्ण विश्व के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीले मेघ के समान जिनका वर्ण है, जिनके सभी अंग अत्यंत सुंदर हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किये जाते हैं, जो सब लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म-मरणरूप भय को दूर करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति, कमलनयन, भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ !



तुलसी विवाह

भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी के मिलन का पर्व तुलसी विवाह हिन्दू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है. देवप्रबोधिनी एकादशी के दिन सभी लोग घरों को साफ-सफाई करते हैं और रंगोली सजाते हैं. शाम के समय तुलसी मैया के पास गन्ने का मंडप सजाकर उसमें लक्ष्मी नारायण स्वरूप शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं और फिर विधि-विधानपूर्वक उनके विवाह को संपन्न कराते हैं. पौराणिक कथा-अनुसार एक बार सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से भगवान विष्णु ने राजा जालंधर की पत्नी वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया. इस पर सती वृंदा ने उन्हें श्राप दे दिया और भगवान विष्णु पत्थर बन गए, जिस कारणवश एक को शालिग्राम भी कहा जाता है और भक्तगण इस रूप में भी उनकी पूजा करते हैं. इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु को अपने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी से विवाह करना पड़ा था और उसी समय से तुलसी विवाह का यह अनूठा रस्म प्रत्येक साल मनाया जाता है. तुलसी विवाह के मुहूर्तानुसार पर इस रस्म को करने का बड़ा ही महत्व है. आराधकगण भक्तों के अनुसार इस दिन श्रद्धा-भक्ति और विधिपूर्वक व्रत करने से व्रती के इस जन्म के साथ-साथ पूर्वजन्म के भी सारे पाप मिट जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है.

तुलसी विवाह विधि

हिन्दू पुराणों में तुलसी जी को विष्णु प्रिया कहा गया है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी जी और भगवान विष्णु का विवाह कराने की प्रथा है। इस विवाह में तुलसी के पौधे और विष्णु जी की मूर्ति या शालिग्राम पाषाण का पूर्ण वैदिक रूप से विवाह कराया जाता है। इस वर्ष तुलसी विवाह का शुभ दिन 13 नवंबर 2013 है। तुलसी विवाह के दिन व्रत करें और तुलसी जी के साथ विष्णु जी की मूर्ति घर में स्थापित करें। इसके बाद सुयोग्य पंडित या ब्राह्मण की सहायता से विधिवत रूप से तुलसी विवाह संपन्न कराएं। द्वादशी के दिन पुनः तुलसी जी और विष्णु जी की पूजा करें और व्रत का पारण करें। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वयं गिरे हुए पत्तों को खाना शुभ होता है।

भगवान विष्णु-लक्ष्मी के निकट जलाएं दीपक

शास्त्रों में कार्तिक मास को बैठ मास माना गया है। मासों में कार्तिक मास, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ श्रेष्ठतमम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलियुग में अत्यंत दुर्लभ हैं। अर्थात कार्तिक मास के समान कोई भी मास नहीं है। पुराण में वर्णित है कि यह मास धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की देने वाला है। विशेष रूप से स्नान दान एवं तुलसी की पूजा इस मास में विशेष फलदायी है। कार्तिक मास में दीपदान करने से पाप नष्ट होते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि इस मास में जो व्यक्ति देवालय, नदी के किनारे, तुलसी के समक्ष एवं शयन कक्ष में दीपक जलाता है उसे सर्व सुख प्राप्त होते हैं। इस मास में भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी के निकट दीपक जलाने से अमिट फल प्राप्त होते हैं। इस मास में की गई भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी की उपासना असीमित फलदायी होती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी की तिथि को देव शयन करते हैं और इस कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उठते हैं। इसीलिए इसे देवोत्थान (देवउठनी) एकादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु, जो क्षीरसागर में सोए हुए थे, चार माह उपरान्त जागे थे। विष्णुजी के शयन काल के चार मासों में विवाहादि मांगलिक कार्यों का आयोजन करना निषेध है। हरि के जागने के बाद ही इस एकादशी से सभी शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। इस दिन गंगा-स्नान, दीपदान, अन्य दानों आदि का विशेष महत्व है।

ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अग्नि और आदित्य ने इसे नवपुनीत पर्व कहा है। इसलिए इसमें गंगा स्नान, दीपदान, सोम, यज्ञ तथा उपासना आदि का विशेष महत्व है। कहा गया है कि यदि स्नान में कुशा और दान करते समय हाथ में जल न जल करते समय संख्या का संकल्प नहीं किया जाए तो कर्म फल की प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए इस दिन स्नान करते समय पहले हाथ-पैर धो लें फिर आचमन करके हाथ में कुशा लेकर स्नान करें, इसी प्रकार दान देते समय हाथ में जल लेकर दान करें। आप यज्ञ और जप कर रहे हैं तो पहले संख्या का संकल्प कर लें फिर जप और यज्ञादि कर्म करें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

पीएम मोदी का तीन दिवसीय दौरे पर मनीला पहुंचे

मनीला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को फिलीपींस के तीन दिवसीय दौरे पर मनीला पहुंचे। इस दौरान मनीला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फिलीपींस के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी के स्वागत में कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पीएम मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय व वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करना है। पीएम मंगलवार को 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वह फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर वहां पहुंचे हैं। मनीला रवाना होने से पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आसियान देशों के साथ भारत के संबंध उसकी एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में हैं।

मथुरा से भाजपा बुनेगी मिशन-2027 का तानाबाना

मथुरा। विधानसभा चुनाव-2027 में जीत की हैट्रिक लगाने के लक्ष्य के साथ भाजपा सोमवार से श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा के परखम में दो दिवसीय चिंतन बैठक करने जा रही है। फरह के पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो अनुसंधान केंद्र में होने वाले इस महामंथन में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं समेत करीब 50 दिग्गज शामिल होंगे। बैठक में चुनावी रणनीति के साथ संगठन की कमजोरियों, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और बूथ प्रबंधन की समीक्षा होगी। पार्टी का मकसद चुनाव से पहले प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में अपनी तैयारियों को व्यवस्थित करना है। इस बार भाजपा ने दूसरे राज्यों के अनुभवी संगठन नेताओं को भी उत्तर प्रदेश की चुनावी जिम्मेदारी देने की योजना बनाई है।मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश-तेलंगाना, झारखंड और महाराष्ट्र के संगठन पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है।

उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की शुरुआत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनगणना-2027 के दूसरे चरण के तहत स्वगणना और घर-घर जाकर जनगणना करने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए कहा कि गणना में समाज का कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सही और सटीक आंकड़े ही प्रदेश के समग्र विकास की योजनाओं का आधार बनेंगे। मुख्यमंत्री ने लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जनगणना के आंकड़ों से यह तय करने में मदद मिलेगी कि प्रदेश में कहां स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों में छूटने वाला व्यक्ति कई बार सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित रह जाता है। आदित्यनाथ ने बताया कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से इस बड़े अभियान की शुरुआत हो रही है। प्रदेश में 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना की प्रक्रिया चलेगी।

आजम खान को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि गाजियाबाद कोर्ट ने उन्हें 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वह 26 नवंबर तक हिरासत में रहेंगे। सपा नेता को डासना जेल में रखा जाएगा। ईडी उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच कर रहा है। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत, 31.10.2026 को मोहम्मद आजम खान को गिरफ्तार किया था। आजम खान मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के संस्थापक और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को कुर्क कर लिया है, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत लगभग 1,170 करोड़ रुपये आंकी गई है। जौहर नगर गांव में स्थित यह यूनिवर्सिटी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की है।

अजित पवार को याद कर भावुक हुए अमित शाह

पुणे। दिवंगत एनसीपी नेता अजीत पवार की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दादा का अचानक और असामयिक निधन एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। उन्होंने अजित पवार के असामयिक निधन को न केवल महाराष्ट्र, बल्कि विशेष रूप से पुणे, बारामती, पिंपरी और चिंचवड़ क्षेत्रों के लिए अपूरणीय क्षति बताया। गृह मंत्री ने कहा कि दादा के अचानक चले जाने से जो खालीपन पैदा हुआ है, उसे कभी भरा नहीं जा सकता। दशकों तक सामूहिक प्रयास करने के बावजूद उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति का ले पाना असंभव लगता है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से भी अजित पवार का निधन उनके लिए अपूरणीय क्षति है। दादा केवल उनके करीबी मित्र ही नहीं थे, बल्कि सच्चे सहयोगी भी थे। उनके जाने से देश ने एक जननेता खो दिया है। अमित शाह ने अजित पवार के राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें विकास की गहरी समझ थी। पंचायती राज, सहकारिता, कृषि और आधुनिक शहरी विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें व्यापक अनुभव हासिल था। उन्होंने कहा कि अजित पवार दूरदृष्टि और विजन रखने वाले नेता थे।

फिलिबेक के बयान पर सियासी घमासान

राहुल गांधी भारत-विरोधी ताकतों को ला रहे एक साथ : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने सोमवार को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम के जरिए कथित भारत विरोधी ताकतों को मंच दिया और देश को बदनाम करने तथा अस्थिरता फैलाने की कोशिश की। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने 14 नवंबर को हुए भारत समिट को एंटी इंडिया समिट करार दिया।

उन्होंने कहा कि इस आयोजन को विपक्ष के नेता की ओर से आयोजित भारत-विरोधी सम्मेलन (एंटी इंडिया समिट) कहना ज्यादा उचित होगा। भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों को एक साथ लाने में जुटे हैं। उनके मुताबिक, राहुल गांधी ऐसा कोई मंच नहीं छोड़ते, जहां से भारत को बदनाम करने, अव्यवस्था फैलाने और देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा सके।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, पार्टी शासित राज्यों में होने वाले निवेश सम्मेलनों में विदेशी निवेशकों और विचारकों को आमंत्रित किया जाता है। इन कार्यक्रमों में निवेश के अवसरों पर चर्चा होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था तथा देश के स्थिर माहौल को सामने रखा जाता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्य में आयोजित कार्यक्रम में देश के हितों को पीछे रख दिया गया। भाटिया ने कहा कि जिस मंच का इस्तेमाल भारत और तेलंगाना को मजबूत करने के लिए होना चाहिए था, उसका उपयोग भारत को कमजोर करने, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने और देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए किया गया।

गौरव भाटिया ने भारत समिट में शामिल हुए यूरोपीय सोशलिस्ट्स पार्टी के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिलिबेक को ऐसे मंच से वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा लगाने का अवसर दिया गया।

भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत में इसी तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन अब एक विदेशी नागरिक ने भारतीय मंच से देश के जनादेश का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी दूसरे देश का नागरिक भारत के जनादेश पर सवाल उठा रहा है।

भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी को अराजक, अपरिपक्व, पार्ट टाइम और राष्ट्रविरोधी विपक्ष का नेता बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का इस पद पर होना देश का दुर्भाग्य है। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि भारत समिट का इस्तेमाल देश की छवि को नुकसान पहुंचाने और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए किया गया। हालांकि, ये सभी आरोप भाजपा प्रवक्ता की ओर से लगाए गए हैं।

भाजपा ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारतीय अर्थव्यवस्था को %मृत% बताने वाले बयान पर पलटवार किया। पार्टी ने गोल्डमैन सैक्स के अनुमान का हवाला देते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2027 में 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी अधिक है। राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि मोदी सरकार के शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था मृत हो गई है।

भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत बताते हैं, लेकिन गोल्डमैन सैक्स के अनुमान उनके दावों की पोल खोलते हैं। उन्होंने कहा, भारत के लिए 2027 में 7.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान है। वहीं, चीन के लिए 4.5 प्रतिशत, अमेरिका के लिए 2.4 प्रतिशत और यूरो क्षेत्र के लिए 0.9 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया गया है।

भंडारी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत %नाजुक% अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि देश की विकास यात्रा में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा, आगे बढ़ते रहो और नई ऊंचाइयां हासिल करते रहो।

राहुल गांधी मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की लगातार आलोचना करते रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार की नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है। वह सरकार के आर्थिक प्रबंधन पर निशाना साधते हुए मृत अर्थव्यवस्था शब्द का इस्तेमाल भी करते रहे हैं।

पिछले साल राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर की गई आलोचना का समर्थन करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को छोड़कर हर कोई जानता है कि देश की अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है।

यूपी चुनाव में कांग्रेस के साथ सीट-बंटवारे पर अखिलेश यादव ने कहा

जो भी पार्टी जीतने की स्थिति में होगी, उसे सीट मिलेगी

मैनपुरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक आने के साथ, समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ सीट-बंटवारे पर बातचीत आगे बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सीट उस पार्टी को मिलेगी जो जीतने की स्थिति में होगी।

मैनपुरी में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी। हम हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं फिर दोहराता हूँ कि दोनों पार्टियाँ मिलकर तय करेंगी कि कौन सी पार्टी जीतने की स्थिति में है। जिस पार्टी के पास किसी सीट को जीतने का बेहतर मौका होगा, उसे वह सीट दी जाएगी।

इससे पहले, यादव ने बताया कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सीट-बंटवारे के समझौते के तहत कांग्रेस ने 181 सीटों की मांग की है। हालाँकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और स्पष्ट किया कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराना ही इस गठबंधन का मुख्य लक्ष्य है।

कांग्रेस सोमवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। इस बैठक में 2027 के चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र-वार तैयारियों, सीट-बंटवारे और राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होने की उम्मीद है।

इस बैठक में राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, आराधना मिश्रा और इमरान मसूद शामिल होंगे। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 17 नवंबर को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट-बंटवारे को लेकर बातचीत होनी है। चर्चा में कांग्रेस की उस कथित मांग पर भी बात हो सकती है, जिसमें उसने राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटें मांगी हैं।

इस बीच, विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों ने जाति समूहों को एकजुट करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है।

रविवार को सपा ने आगरा में एक दलित सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हुए। वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बीजेपी का राजनीतिक आधार खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मकसद सिर्फ बीजेपी को हराना नहीं, बल्कि उसे राजनीति से हमेशा के लिए खत्म करना है।

वहीं, एसबीएसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने आगरा में हुए सपा के दलित सम्मेलन की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, उनके अपने ही नेता दलितों पर अत्याचार, बड़े पैमाने पर लूटपाट और उनकी जमीनों पर अवैध कब्जे के लिए जिम्मेदार थे।

अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीट-बंटवारे के किस फॉर्मूले पर सहमत होती हैं। इससे पहले, सपा के एक सांसद की टिप्पणी ने भी सबका ध्यान खींचा था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश चुनावों में कांग्रेस को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी।

खेल
प्रमुख समाचार

जय शाह फिर बने आईसीसी अध्यक्ष, निर्विरोध हुआ चयन

नई दिल्ली। जय शाह लगातार दूसरी बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष बन गए हैं। जय शाह को निर्विरोध आईसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित आईसीसी बोर्ड की बैठक के दौरान निदेशकों के प्रस्ताव के बाद बोर्ड ने उनके दूसरे कार्यकाल पर मुहर लगा दी। इस फैसले को क्रिकेट के वैश्विक विस्तार और खेल के भविष्य की योजनाओं के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

जय शाह के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए आईसीसी बोर्ड ने उन्हें एक और कार्यकाल की जिम्मेदारी सौंपी है। क्रिकेट इस समय वैश्विक स्तर पर अपने विस्तार, प्रशंसकों की बढ़ती संख्या और व्यावसायिक विकास के नए दौर से गुजर रहा है। इसके अलावा, लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट की वापसी भी इस खेल के लिए एक बड़ा अवसर मानी जा रही है। आईसीसी ने हाल ही में प्रतियोगिताओं के लिए अपने दीर्घकालिक कार्यक्रम का भी विस्तार किया है, जिससे खिलाड़ियों को अधिक मौके और क्रिकेट के विकास के नए रास्ते मिल सकेंगे। बोर्ड ने क्रिकेट की बुनियादी संरचना को मजबूत करने, महिला क्रिकेट के विकास को गति देने और एसोसिएट सदस्यों के लिए अवसर बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने तथा खेल के भविष्य के लिए बेहतर व्यावसायिक अवसर विकसित करने पर जोर दिया गया। दूसरी बार आईसीसी अध्यक्ष चुने जाने पर जय शाह ने कहा, आईसीसी बोर्ड ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, उससे मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। सभी निदेशकों के निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए मैं उनका आभारी हूं। आईसीसी के चेयरमैन के रूप में काम करना मेरे लिए सम्मान के साथ-साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स ने लगाई 512 अंकों की छलांग, निफ्टी 25290 के ऊपर

नई दिल्ली। शेयर बाजार में हफ्ते की शुरुआत जोरदार रैली के साथ हुई। आज के कारोबारी सत्र के आखिरी में तेजी के साथ कारोबार बंद हुआ। सेंसेक्स 512 अंक चढ़कर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 25,290 के ऊपर टिका रहा। आईटीसी और टाटा कंज्यूमर जैसे शेयरों में 3-3 फीसदी की दमदार तेजी देखने को मिली। बाजार में आज तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 512 अंक चढ़ गया, जबकि एनएसई निफ्टी बढ़त के साथ 25,300 अंक के करीब पहुंच गया। वित्तीय, एफएमसीजी और तेल एवं गैस कंपनियों के शेयरों में खरीदारी, विदेशी निवेशकों की लगातार लिवाली और क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट से बाजार को सपोर्ट मिला।बीएसई सेंसेक्स 512.34 अंक यानी 0.63 प्रतिशत बढ़कर 82,104।79 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 719.20 अंक चढ़कर 82,311.65 अंक पर पहुंच गया था।

अक्टूबर में थोक महंगाई बढ़कर 12.29% पर पहुंची

नई दिल्ली। ईंधन एवं बिजली, खाद्य पदार्थों, खनिजों और गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से थोक मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 12.29 प्रतिशत हो गई। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में 11.39 प्रतिशत थी। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 8.26 प्रतिशत रही जो पिछले महीने 8.14 प्रतिशत थी। गैर-खाद्य वस्तुओं की महंगाई पिछले महीने 11.69 प्रतिशत रही, जबकि सितंबर में यह 10.28 प्रतिशत थी। खनिजों में कीमतों में वृद्धि की दर 12.64 प्रतिशत रही जो सितंबर में 9.51 प्रतिशत थी। कुल मिलाकर, प्राथमिक वस्तुओं की श्रेणी में थोक महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 9.24 प्रतिशत हो गई, जो पिछले महीने 8.67 प्रतिशत थी। ईंधन व बिजली की महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 32.84 प्रतिशत हो गई, जो पिछले महीने 25.85 प्रतिशत थी।

गोल्ड माइनिंग को बढ़ावा देगा नीति आयोग

नई दिल्ली। भारत में सोने की लगातार बढ़ती मांग और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए नीति आयोग जल्द ही गोल्ड एक्सप्लोरेशन और माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए एक खास ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है। इसके तहत देश में सोने की खोज और खनन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, नियामकीय प्रक्रियाओं में सुधार और निजी निवेश आकर्षित करने जैसे कदम उठाए जाने की संभावना है। भारत में हर साल सोने का आयात बड़े पैमाने पर होता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर दबाव पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग के इस प्रस्तावित फ्रेमवर्क में गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट्स को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार लंबी अवधि के खनन अधिकार देने, निवेशकों की योग्यता और तकनीकी क्षमता के आधार पर उनकी रेटिंग करने तथा परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया आसान बनाने जैसे उपायों पर विचार कर सकती है।

महानदी कोलफील्ड्स का आईपीओ 19 को खुलेगा

नई दिल्ली। कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने अपने 8,981 करोड़ रुपए के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए 129-136 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। ओडिशा स्थित महानदी कोलफील्ड्स की सोमवार को जारी सार्वजनिक घोषणा के अनुसार, निर्गम 19 नवंबर को अभिदान के लिए खुलेगा और 23 नवंबर को बंद होगा। बड़े (एंकर) निवेशक 18 नवंबर को बोली लगा पाएंगे। कंपनी के अनुसार, यह आईपीओ पूरी तरह बिक्री पेशकश (ओएफएस) पर आधारित है। इसके तहत प्रवर्तक कोल इंडिया 66.18 करोड़ शेयर बेचकर अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी कम करेगी। निर्गम पूरी तरह ओएफएस होने के कारण एमसीएल को आईपीओ से कोई राशि नहीं मिलेगी।

बिजली की बढ़ती मांग के बीच भारत को बनाना होगा अपना बैटरी उद्योग

लवीश भंडारी

भारत में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसकी रफ्तार लगभग देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में होने वाली वृद्धि के बराबर है। अनुमान है कि अगले 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार मौजूदा स्तर से पांच से छह गुना तक बढ़ सकता है। ऐसे में ऊर्जा की मांग भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। खास बात यह है कि भविष्य में देश की अधिकांश आर्थिक गतिविधियां बिजली पर निर्भर होंगी। ऐसे में आने वाले वर्षों में बिजली उत्पादन की क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की जरूरत होगी।

इस बढ़ती मांग को पूरा करने में अक्षय ऊर्जा, खासतौर पर सौर और पवन ऊर्जा की अहम भूमिका होगी। ये ऊर्जा के अपेक्षाकृत सस्ते स्रोत हैं और आने वाले समय में इनकी लागत और कम होने की संभावना है। लेकिन इनके साथ एक बड़ी चुनौती भी जुड़ी है।

इनके जरिये हर समय एक समान बिजली नहीं मिलती जबकि बिजली की मांग भी दिन और रात के अलग-अलग समय पर बदलती रहती है। ऐसे में बिजली की आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाए रखना बिजली वितरण कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है।

बिजली की रुक रुक कर होने वाली आपूर्ति और मांग में उतार-चढ़ाव जैसी समस्या का समाधान, ऊर्जा भंडारण की ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जिसमें जरूरत के समय के लिए बिजली जमा करके रखी जा सके और मांग बढ़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके।

अच्छी बात यह है कि बिजली भंडारण के लिए कई तरह की तकनीकें उपलब्ध हैं जो मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम कर सकती हैं। इनमें पानी, संपीडित हवा और खारे घोल पर आधारित तकनीकें शामिल हैं लेकिन इन सभी को बड़े पैमाने पर विकसित

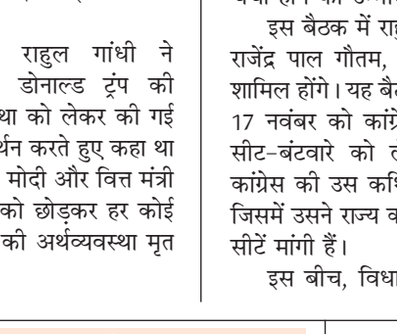

करने में कई व्यावहारिक कठिनाइयां हैं।

दूसरी ओर, लीथियम-आयन बैटरियां दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली वैकल्पिक तकनीक हैं, लेकिन इनके उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का मजबूत नियंत्रण है। ऊर्जा भंडारण की हर तकनीक की अपनी खूबियां और सीमाएं हैं। इनका इस्तेमाल धीरे-धीरे बढ़ रहा है लेकिन अभी ये बड़े पैमाने पर व्यावसायिक रूप से स्थापित नहीं हो पाई हैं। यदि इनका उत्पादन बड़े स्तर पर शुरू हो जाए तो लागत में बड़ी कमी आ सकती है। इसके अलावा, बड़े औद्योगिक ढांचे के विकास से शोध, तकनीकी नवाचार और निवेश के लिए भी अधिक संसाधन जुटाए जा सकते हैं।

यही वह क्षेत्र है, जहां भारत के सामने औद्योगिक नीति बनाने का एक बड़ा अवसर और चुनौती दोनों मौजूद हैं। इसके लिए भारत के सामने मोटे तौर पर तीन विकल्प हैं। पहला, किसी एक तकनीक को प्राथमिकता देने के बजाय सभी प्रकार की बैटरी और ऊर्जा भंडारण तकनीकों को समान अवसर देना। फिलहाल देश की नीति, इसी दिशा में आगे बढ़ रही है।

दूसरा विकल्प यह है कि सरकार लीथियम-आयन बैटरियों को बढ़ावा देने से पीछे हटे और दूसरी तकनीकों के विकास के लिए रास्ता खोले ताकि बाजार अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प चुन सके।

तीसरा विकल्प यह है कि सरकार किसी एक खास तकनीक का चयन करे और उसके विकास तथा उत्पादन के लिए निवेश को प्रोत्साहित करे।

भारत के सामने समस्या यह है कि यदि देश लीथियम-आयन बैटरियों पर ही निर्भर रहता है तब अगले एक दशक या उससे भी अधिक समय तक उसे चीन पर निर्भर रहना पड़ सकता है। ऐसे में भारत को ऐसी औद्योगिक नीति की जरूरत है जो ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में एक नए घरेलू उद्योग के विकास का रास्ता तैयार करे।

इस दिशा में एक प्रभावी औद्योगिक नीति के तीन प्रमुख पहलू होने चाहिए। पहला, नीति का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। भारत को यह तय करना होगा कि वह किस तरह की आयात निर्भरता से बचना चाहता है। इस मामले में लक्ष्य लीथियम-आयन बैटरियों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना हो सकता है। दूसरा, सरकार को वैकल्पिक तकनीकों के विकास और उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए सोडियम-आयन बैटरियों जैसी तकनीकों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

महादेव घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ छठ महापर्व





36 घंटे के निर्जला उपवास के बाद व्रतियों ने किया पारण

महादेव घाट पर उमड़ी आस्था की भीड़, छठी मैया के गीतों से भक्तिमय हुआ माहौल

सुख, समृद्धि, और खुशहाली की कामना के साथ छठ मनाया गया

रायपुर। राजधानी रायपुर के महादेव घाट पर छठ महापर्व के अंतिम दिन आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो गया और व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास भी पूरा हो गया। महादेव घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। व्रती महिलाएं और पुरुष सूप में फल, ठेकुआ तथा अन्य पूजन सामग्री लेकर घाट पहुंचे और खारुन नदी के जल में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान छठी मैया के पारंपरिक गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। बड़ी संख्या में व्रतियों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। महादेव घाट के साथ ही शीतला तालाब, तेलीबांधा तालाब, बूढ़ातालाब और बोरियाखुर्द सहित शहर के विभिन्न छठ घाटों पर भी सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ रही। छठ पूजा को लेकर सभी प्रमुख घाटों को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। विभिन्न घाटों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ताकि पूजा के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

उल्लेखनीय है कि छठ महापर्व के तीसरे दिन रविवार की शाम व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया था। इसके बाद सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय छठ पर्व का समापन हुआ। पारण के साथ ही व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास समाप्त किया। पूरे प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ छठ महापर्व मनाया गया।

महादेव घाट में उगते सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि यह चार दिनों का महापर्व होता है। पहले दिन नहाए खाए से पर्व की शुरुआत होती है. दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम आयोजित होता है और तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य की उपासना करने के साथ ही उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। उत्तर भारतीयों के द्वारा यह छठ महापर्व सालों से करते आ रहे हैं उनका कहना है कि घर में सुख,शांति समृद्धि, खुशहाली, तरक्की पति और बच्चों की दीर्घायु की कामना के लिए की जाती है. छठ महापर्व में छठी मैया के लिए उपवास व्रत निर्जला रखा जाता है. यह काफी कठिन व्रत होता है। जिसको महिलाओं के द्वारा चार दिनों तक रखना होता है।



सिंधी पंचायत का दीपावली मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह हर्षोल्लास से सम्पन्न

रायपुर। पूज्य सिविल लाइंस सिंधी पंचायत द्वारा आयोजित दीपावली मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। समारोह में समाज के सैकड़ों परिवारों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान झूलेलाल साहिब की पूजा-अर्चना एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। भगवान झूलेलाल की आरती महिला विंग अध्यक्ष मधु बहादुर आर्त्तवानी, लक्ष्मी छुगानी, रेनू आहूजा, मीनू रामनानी,रश्मि वाधवा, सोनम नजरानी, निकिता पारवानी,सपना बजाज, महिला टीम के सदस्यों द्वारा की गई। इस अवसर पर पंचायत अध्यक्ष संजय जेसिंध ने स्वागत उद्बोधन देते हुए समाज की एकता एवं बच्चों को शिक्षा और संस्कार से जोड़ने पर जोर दिया।

श्रेष्ठ भारत रंगोली प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरित, डुबिना साहू ने मारी बाजी



रायपुर। महाकोशल कला परिषद, रायपुर एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डंगनिया के संयुक्त तत्वावधान में श्रेष्ठ भारत रंगोली प्रतियोगिता-2026 का पुरस्कार वितरण समारोह डंगनिया स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सम्पन्न हुआ। संकुल स्तरीय रंगोली प्रतियोगिता में 10 विद्यालयों के शासकीय, अशासकीय शाला के 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसके परिणाम निर्णायक समिति डॉ प्रवीण शर्मा, डॉ प्रिया राठौर एवं डॉ शिखर शर्मा द्वारा घोषित किए गए।

प्रथम पुरस्कार - डुबिना साहू, सावित्रीबाई फुले एजुकेशनल एकेडमी, डंगनिया, रायपुर। **द्वितीय पुरस्कार** - तृप्ति विश्वकर्मा, गायत्री कान्वेंट स्कूल, डंगनिया, रायपुर एवं शताक्षी साहू, सावित्रीबाई फुले एजुकेशनल एकेडमी, डंगनिया, रायपुर। **तृतीय पुरस्कार** - मीरा वर्मा, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, डंगनिया, रायपुर एवं ईशिका यदु, सावित्रीबाई फुले एजुकेशनल एकेडमी, डंगनिया, रायपुर एवं संध्या ध्रुव, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, डंगनिया, रायपुर।

सिलतरा में जब्त नशे का जखीरा नष्ट, 234 किलो गांजा समेत टेबलेट और एमडीएमए फर्नेस में जलाया गया

एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा समेत ड्रग डिस्पोजल कमेटी की मौजूदगी में हुई कार्रवाई



रायपुर। सिलतरा स्थित जायसवाल नेको प्लांट में जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की मौजूदगी में 234 किलोग्राम गांजा, 326 नग प्रतिबंधित टेबलेट और 12 ग्राम MDMA को विधिसम्मत तरीके से नष्ट किया गया। 16 नवंबर को रायपुर ग्रामीण के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों में जब्त मादक पदार्थों का अधिनियम में निहित प्रावधानों, न्यायालय के आदेशों एवं शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप विधिसम्मत नष्टीकरण किया गया। केन्द्र सरकार, गृह मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दिशा-निर्देशों एवं एनडीपीएस एक्ट में निहित प्रावधानों के अनुरूप गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा यह कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र श्रीवास्तव, उपायुक्त आबकारी रायपुर डॉ. प्रवीण वर्मा तथा थाना प्रभारियों की उपस्थिति में जायसवाल नेको प्लांट, सिलतरा में नष्टीकरण की कार्यवाही संपादित की गई। नष्टीकरण की कार्यवाही में रायपुर ग्रामीण के थानों से जब्त 234 किलोग्राम गांजा, 326 नग प्रतिबंधित टेबलेट तथा 12 ग्राम MDMA को जनसामान्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय मानकों एवं प्रचलित वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए जायसवाल नेको प्लांट, सिलतरा के फर्नेस में विधिवत् नष्ट किया गया।

रायपुर में गंदगी पर बड़ा एक्शन, निगम के दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राजधानी रायपुर में गंदगी पर कार्रवाई करते हुए रायपुर नगर निगम के दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग ने शहर के कई स्थानों पर गंदगी के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार मानते हुए उपायुक्त (सफाई प्रभारी) जसदेव बाबरा और जोन क्रमांक-4 की आयुक्त दिव्या चंद्रवंशी को नोटिस दिया है। दोनों अधिकारियों को 3 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने दोनों अधिकारियों को जारी नोटिस में कहा है कि प्रत्येक समीक्षा बैठक में नगर की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया जाता रहा है, किन्तु आपके द्वारा वरिष्ठालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपनी कार्य प्रणाली में आशातीत सुधार नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप आए दिन समाचार पत्रों में जगह-जगह गंदगी फैले होने संबंधी समाचार प्रकाशित होते हैं, जो नगर निगम एवं शासन की छवि धूमिल करने के साथ-साथ आपकी कार्य प्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता है। शहर में जगह-जगह फैली गंदगी के लिए प्रथम दृष्टया आप जिम्मेदार प्रतीत होते हैं।

सिलतरा में शराब भट्ठी के सुपरवाइजर ने लगाई फांसी

मां और पत्नी को भेजे अंतिम मैसेज में दफ्तर की प्रताड़ना का जिक्र

दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

शराब भट्ठी प्रबंधन, मैनपावर कंपनी और आबकारी विभाग से जुड़े इस संवेदनशील मामले में पुलिस जल्द ही नामजद आरोपियों और संबंधित अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। इस अचानक हुई घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय स्तर पर भी इस घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है.

रायपुर। राजधानी रायपुर के सिलतरा इलाके से एक बेहद दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया है। सिलतरा बाजार चौक के पास स्थित एक मकान में शराब भट्ठी के सुपरवाइजर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान प्रशांत वर्मा के रूप में हुई है, जो कि मांढर स्थित शराब भट्ठी में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ थे। दर्दनाक कदम उठाने से पहले उन्होंने अपनी मां और पत्नी के मोबाइल पर एक आखिरी संदेश (मैसेज) भेजा था, जिसमें दफ्तर में चल रही गंभीर परेशानियों और प्रताड़ना का स्पष्ट जिक्र किया गया है। मां और पत्नी को भेजा गया अंतिम संदेश प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिलतरा बाजार चौक निवासी प्रशांत वर्मा ने आत्महत्या करने से ठीक पहले अपने मोबाइल से मां और पत्नी को एक संदेश भेजा था। इस मैसेज में उन्होंने मांढर शराब भट्ठी में ही पदस्थ दो अन्य कर्मचारियों पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और उन्हें अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही, संदेश में जोनल आबकारी अधिकारी और मैनपावर कंपनी के अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही सिलतरा थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतक के मोबाइल फोन को जप्त कर लिया गया है और उसमें मिले अंतिम मैसेज तथा उसमें लगाए गए तमाम आरोपों की तकनीकी व मैदानी स्तर पर बारीकी से जांच की जा रही है।

हर साल घटाई जा रही है आदान सहायता, किसानों को प्रति क्विंटल 258 रु. का लगाया जा रहा चूना

किसान कल्याण नहीं, किसानों के हक पर खुली डकैती डाली जा रही है



रायपुर। छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के अधिकारों पर हो रही संगठित और सुनियोजित डकैती के खिलाफ सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार का असली किसान-विरोधी चरित्र अब बेनकाब हो चुका है। एक तरफ खेती की बढ़ती लागत से अन्नदाता त्रस्त है, तो दूसरी तरफ यह सरकार हर साल चुपचाप किसानों के बोनस और आदान सहायता की राशि कम करती जा रही है। वर्ष 2023-24 में जो अंतर की राशि 917 रुपए प्रति क्विंटल थी, उसे घटाते-घटाते आज खरीफ सीजन 2026-27 में मात्र 659 रुपए कर दिया गया है। कांग्रेस सरकार के मुकाबले आज हर किसान के एक एकड़ पर 5,418 रुपए की सीधी डकैती डाली जा रही है। 2023-24 की तुलना में राज्य सरकार का आदान सहायता 258 रुपए प्रति क्विंटल घट गया है। सरकार किसानों का हक मारकर उन पर अहसान जताने का ढोंग कर रही है, जिसे छत्तीसगढ़ का किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि किसानों की हक मारी और भाजपा सरकार के कृषक उन्नति के खोखले दावों की पोल खुल गई है। सरकार एक तरफ कृषक उन्नति योजना और किसानों के कल्याण के ढोल पीट रही है, वहीं धरातल का सच यह है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने सुनियोजित तरीके से किसानों के मिलने वाली सहायता राशि में कैंची चला दी है। लागत मूल्य, डीजल, खाद, कीटनाशक, बीज, बिजली और मजदूरी आसमान छू रहा है, लेकिन सरकार ने किसानों को मिलने वाले बोनस, अंतर की राशि को हर साल कम करके उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है।

मुक्तिबोध राष्ट्रीय नाट्य समारोह का समापन आज 'गुड़िया की शादी' से

मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल की रंग प्रयोगशाला की प्रस्तुति होगी समारोह का अंतिम आकर्षण



रायपुर। छत्तीसगढ़ फिल्म एवं विजुअल आर्ट सोसायटी द्वारा आयोजित पांच दिवसीय 'मुक्तिबोध राष्ट्रीय नाट्य समारोह-2026' का समापन 17 नवंबर को मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल की रंग प्रयोगशाला की नाट्य प्रस्तुति 'गुड़िया की शादी' के साथ होगा। रंगमंदिर, गांधी चौक में शाम 7 बजे होने वाली इस प्रस्तुति के साथ पांच दिनों से जारी रंगमंचीय उत्सव का समापन होगा। समारोह के अंतिम दिन प्रस्तुत होने वाला नाटक 'गुड़िया की शादी' दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण रहेगा। मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल की रंग प्रयोगशाला के कलाकार अपनी रंग प्रस्तुति के माध्यम से समारोह को यादगार विदाई देंगे। देश के विभिन्न शहरों से आए नाट्य दलों और रंगकर्मियों की प्रस्तुतियों ने इस आयोजन को विविध रंगानुभवों से समृद्ध किया है।

उल्लेखनीय है कि 13 नवंबर से शुरू हुए इस पांच दिवसीय समारोह में अब तक नाट्य प्रस्तुतियों और रंग संगीत के जरिए दर्शकों को अलग-अलग विषयों और शैलियों से रूबरू होने का अवसर मिला है। शनिवार को रंग छत्तीसा राजनांदगांव की ओर से पूनम तिवारी एवं साथियों ने रंग संगीत की प्रस्तुति दी, जबकि विवेचना रंगमंडल जबलपुर ने 'पर पाजेब न भीगे' का मंचन किया। रविवार को समानांतर इलाहाबाद की ओर से 'युद्ध नहीं, चाहिए शांति' का मंचन किया जाएगा।

आयोजकों ने रंगमंच, कला और साहित्य में रुचि रखने वाले शहरवासियों से सोमवार और मंगलवार को रंगमंदिर पहुंचकर नाट्य प्रस्तुतियों का आनंद लेने तथा समारोह के समापन का हिस्सा बनने की अपील की है।

328 दिन बाद टूटा सब्र का बांध, डी.एड. अभ्यर्थियों ने परिवार सहित शिक्षा मंत्री के बंगले का किया घेराव

पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झूमाझटकी, हिरासत में



रायपुर. छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर डी.एड. अभ्यर्थियों का संघर्ष लगातार जारी है। पिछले 328 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के सब्र का बांध सोमवार को टूट पड़ा। अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगभग 300 डी.एड. अभ्यर्थी अपने माता-पिता, बच्चों और परिजनों के साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निवास पर पहुंच गए और बंगले का घेराव कर अपनी आवाज बुलंद की। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झूमाझटकी की स्थिति भी बनी। पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचाया। वहां नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।

अभ्यर्थियों का कहना है कि वे कोई नई भर्ती या अतिरिक्त पदों की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत शेष लगभग 2,300 रिक्त पदों पर पात्र डी.एड. अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।

उनका आरोप है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के बाद भी पात्र अभ्यर्थियों को न्यायपूर्ण नियुक्ति नहीं मिल पाई है। वहीं, 26 सितंबर 2025 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित याचिकाओं में दो महीने के भीतर उचित निर्णय लेकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश के बावजूद अभ्यर्थियों को अब तक निश्चित नियुक्ति तिथि नहीं मिली है। अगर हमारे नियुक्ति पर जल्दी निर्णय नहीं लिया गया तो आगे चलकर सभी डीएड अभ्यर्थी मुख्यमंत्री के बंगले पर आत्मदाह करेंगे।

मंत्री से मुलाकात की मांग पर अड़े अभ्यर्थी

प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री की ओर से चार प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए अंदर बुलाने की बात कही गई, लेकिन आंदोलनकारी सभी अभ्यर्थियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ सामूहिक बातचीत तथा नियुक्ति पर ठोस निर्णय की मांग पर अड़े रहे। अभ्यर्थियों का कहना था कि 328 दिनों से संघर्ष कर रहे हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़े इस गंभीर विषय पर केवल चार लोगों से औपचारिक बातचीत पर्याप्त नहीं है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.